उत्तराखण्ड शासन

निदेशालय समाज कल्याण

उत्तराखण्ड में

सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005

के अन्तर्गत निर्धारित 17

मैनुअल का विवरण वर्ष 2005

मैनुअल संख्या - 12 से 17

अनुक्रमणिका

मैनुअल संख्या	मैनुअल	पृष्ठ संख्या
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है की स्थिति	1 से 10
13.	अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राविधकारों के प्राप्तिकर्ताओं की स्थिति।	11 से 46
14.	इलैक्ट्रानिक्स रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	47
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉं, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के जिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।	48
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	49
17.	अन्य सूचना जो विहित की जाय।	50 से 76

मैनुअल

12



खण्ड–12

(निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल)

सहायकी कार्यक्रमों के निश्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है की स्थिति :–

(The manner of execution of subsidy programmes including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.)

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि0 देहरादून द्वारा अनुदान, ऋण की योजना चलाई जा रही है, उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात राज्य में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, विकलागों, सफाई कर्मचारियों एवं स्वच्छकारों की आर्थिक भिन्नता को दूर कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 25.10.2001 को उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया है ।

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है ।

1– अनुसूचित जाति के लिए स्वतः रोजगार योजना का संचालन
2– कौशल वृद्धि योजना
3– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना
   - मियादी ऋण (टर्म लोन)
   - लघु वित्त ऋण योजना
   - कौशल वृद्धि योजना के लिए अनुदान

4– शिल्पी ग्राम योजना
5– स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों की विमुक्ति एवं पुर्नवासन की योजना
6– राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
7– पिछड़ी जाति का आर्थिक विकास
8– राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.)
9– राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
10– राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
11– राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम
12– जनश्री बीमा योजना

उपरोक्त योजनाओं का प्रारूप संलग्न है ।

41. बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें :

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अलपसंख्यकों के विकास हेतु अलग–अलग वित्तीय एवं विकास निगम स्थापित हैं, परन्तु उत्तरांचल के गठन के पश्चात इराके भौगोलिक क्षेत्र व आकार एवं जनसंख्या तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन सभी वर्गों के लिए एक ही बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया है जो केन्द्रीय वित्त निगमों के लिए चेनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है जिसके माध्यम से इन सभी वर्गों के लिए अनुदान एवं मार्जिन मनी की सुविधा विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध कराई जायेगी, निगम द्वारा अनुसूचित कल्याण की निम्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं :

41.1 स्वतः रोजगार योजना :

इस योजना का मूल उद्देश्य प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु बैंकेबुल योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित कर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है, उन्हें स्वतः रोजगार योजना के लिए बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर योजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रुपया 10,000 तक अनुदान एवं 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

41.2 विविध प्रशिक्षण योजना :

अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों एवं अनुसूचित के व्यक्तियों की कौशल वृद्धि हेतु उनहें उनकी अभिरुचि के अनुसार उद्योग, सेवा, व्यवसाय एवं कृषि क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में ट्राईसेम पेटर्न पर प्रशिक्षण शासकीय/अर्द्धशासकीय स्वायतशासी स्वयं संस्थाओं के माध्यम से अधिकतम 6 माह का दिया जाता है। प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षणार्थियों को ट्राईसेम योजना में निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

41.3 शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना :

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत उपयुक्त व्यवसायिक क्षेत्रों में रु0 38,000 प्रति दुकान की लागत के आधार पर अनुसूचित के गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले बेरोजगार उद्यमियों को उनकी निजी भूमि पर तीन किश्तों में उपलब्ध कराकर 13 X '11 वर्ग फीट की दुकान निर्मित करायी जायेगी। निर्मित दुकानों पर व्यवसाय स्थापित करने हेतु निगम के माध्यम से संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है उसके निर्माण लागत में रु. 6000 अनुदान एवं शेष धनराशिं 10 वर्षों में वापस यिके जाने वाला ब्याज मुक्त ऋण होता है।

41.4 परिसम्पत्ति निर्माण योजना :

इस योजना के अनतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु परिसम्पत्ति सृजन कराई जाती है, कृषि भूमि भी क्रय कर आवंटित की जाती है, ताकि व्यक्ति स्वावलम्बी होकर धनोपार्जन कर सके।

41.5 अनु0 जातियों हेतु मार्जिन मनी ऋण :

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 20,000 से बड़ी योजनाओं में 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर योजना का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण प्रदान किया जाता है। इस हेतु निगम की अंश पूंजी से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

41.6 स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता :

बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियें हेतु स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार योजना, दुकान निर्माण योजना, परिसम्पति योजना, विविध प्रशिक्षण योजना तथा मार्जिन मनी ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 के में रुपये 476.08 लाख की धनराशि से 5147 लाथार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2005–06 के माह फरवरी, 2006 तक रु0 473.78 लाख व्यय कर 4225 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में योजना के अन्तर्गत 650.00 लाख रुपये धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है जिससे लगभग 6500 व्यक्तियों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

41.7 जीविकास अवसर प्रोत्साहन योजना :

अनुसूचित जाति के व्यक्तियें को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में इस योजनान्तर्गत रुपये 682.00 लाख की धनराशि से 1650 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2005–06 के माह फरवरी, 2006 तक रु0 235.55 लाख व्यय कर 300 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु इस योजना के अन्तर्गत 500.00 लाख रुपये धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है जिससे लगभग 5000 व्यक्तियों को लाभान्वित होने का अनुमान है।

41.8 शिल्पी ग्राम योजना :

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अकुशल कारीगरों को उन्हीं ग्रामों के दक्ष कारीगरों द्वारा प्रशिक्षित कर स्थानीय शिल्प का उत्पादन एवं विपणन की व्यवस्था की दृष्टि से योजना का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में इस योजनान्तर्गत रु. 81.17 लाख की धनराशि का व्यय कर 230 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया हैं वित्तीय वर्ष 2005–06 के माह फरवरी, 2006 तक रु. 82.99 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु रु. 200.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित कर 2000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का अनुमान है।

भारतीय जीवन बीमा निगम

पेंशन एवं समूह बीमा इकाई, न्यू कनाट प्लेस, द्वितीय तल मण्डल कार्यालय, देहरादून।

सामूहिक बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत)

जनश्री मास्टर पालिसी सं0.....

दावा प्रपत्र

(दावेदार द्वारा भरा जायेगा)

खण्ड (अ)

1– मृत सदस्य का नाम एवं पता :.....

2– नोडल एजेंसी का नाम एवं पता :.....

3– सदस्यता क्रमांक :.....

4– योजना में प्रवेश की तिथि :.....

5– पिता/पति का नाम :.....

6– (अ) मृत्यु का दिनांक :.....

(ब) मृत्यु के समय आयु :.....

(स) मृत्यु का स्थान :.....

(द) मृत्यु का कारण : .....

7– नामित व्यक्ति का नाम, आयु एवं पूर्ण पता:.....

8– मृतक सदस्य से सम्बन्ध :.....

9– नामित का बैंक (पते सहित) तथा बचत खाता सख्या : .....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त वर्णित सभी प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक रूप से पूर्णतया सत्य हैं।

नाम : ..... नामित के हस्ताक्षर

पता : ..... स्थान : .....

दिनांक : .....

खण्ड–ब **(नोडल एजेन्सी द्वारा पूर्ण करने हेतु)**

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर पूर्णतया सत्य हैं एवं उपरोक्त नामित नामांकन पंजिका में क्रम सं0.....पर पंजीकृत है।

नोडल एजेन्सी के हस्ताक्षर नोडल एजेन्सी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

खण्ड–स **(भुगतान रसीद)**

मैं/हम.....एतद्द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से रु0.....

.....(शब्दों में.....) जो जनश्री बीमा योजना में स्वद्ध श्री/श्रीमती.....

.....के मृत्यु दावे की बीमा धनराशि का पूर्ण एवं अंतिम बंटवारे के रूप में पावती देते हैं।

नोडल एजेन्सी की मोहर

रसीदी टिकट

नोडल एजेन्सी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

खण्ड–द

कृपया दावा भुगतान राशि नामित के .....बचत बैंक का नाम एवं पता.....

.....बचत खाता सं0).....में जमा कराने हेतु प्रेषित करें।

नोडल एजेन्सी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुसूचित जातियों का विवरण

1. अकरिया
2. अधिक
3. आदी
4. आहेलिया
5. बैगा
6. बैसवार
7. बैजनिया
8. बाजगी
9. बलहार
10. बलई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुष
14. बांस फोड
15. बखार
16. बसोड़
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भांतू
21. भुईया
22. भुइयार
23. बोरिया
24. चमार, धूसिया, झुसिया, जाटव
25. चेरो
26. दवगर
27. धनगर
28. धानुक
29. धारका
30. धोबी
31. डोम
32. डोगर
33. दुसाध
34. धरागी
35. धसिया
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हवूड़ा
39. हेरी
40. हेला
41. कलावाज
42. कंजर
43. कपड़िया
44. कखल
45. खैराहा
46. खरवार (बनवासी को छोड़कर)
47. खटिक
48. खोरोत
49. कोल
50. कोरी
51. कोखा
52. लालबेरी
53. मझवार
54. मजहवी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. परहिया
59. पासी, तरमाली
60. पाटरी
61. रावत
62. सहरिया
63. रिनौढ़िया
64. सांसिया
65. शिल्पकार
66. तुरैहा

अनुसूचित जनजातियों का विवरण

1. थारू
2. बोक्सा
3. भोटिया
4. राजी
5. जौनसारी

पिछड़ी जातियों का विवरण (पूर्ववर्ती राज्य में अधि सूचित)

1. अहीर
2. अरख
3. काछी
4. कहार
5. केवट या मल्ल
6. किसान
7. कोइरी
8. कुम्हार
9. कुर्मी
10. कम्बोज
11. कसगर
12. कंजड़ा या राइन
13. गोसाई
14. गूजर
15. गडेरिया
16. गद्दी
17. गिरि
18. चिकवा (कास्साब)
19. छीपी
20. जोगी
21. झोजा
22. दफाली
23. तमोली
24. तेली
25. दर्जी
26. धीवर
27. नक्काल
28. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में)
29. नायक
30. फकीर
31. बंजारा
32. बढ़ई
33. बारी
34. बैरागी
35. बिन्द
36. बियार
37. भर
38. भुर्जी या भड़भूजा
39. भठियारा
40. माली, सैनी
41. मनिहार
42. मुराव या मुराई
43. मोमिन (अंसार)
44. मिरासी
45. मुस्लिम कायस्थ
46. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
47. मारछा
48. रंगरेज
49. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी–राजपूत
50. लोहार
51. लोनिया
52. सोनार
53. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित न हों)
54. हलवाई
55. हज्जाम (नाई)
56. राय सिक्ख
57. सक्का–भश्ती, भिश्ती–अब्बासी
58. धोबी (जो अनुसूचित जातियो/जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
59. कसेरा/ठठेरा, ताम्रकार
60. नानबाई
61. मीर शिकार
62. शेख सरवरी (पिराई) पौराही
63. मेर मेवाती
64. कोष्टा/कोष्टी
65. रोड
66. खुमरा, संगतराश, हसोरी
67. मोची
68. खागी
69. तंवर सिंघाड़िया
70. कतुआ
71. माहीगीर
72. दांगी
73. धाकड़
74. गाड़ा
75. तंतवा
76. जोरिया
77. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
78. जाट
79. कलाल, कलवार, कलार

उत्तरांचल राज्य में निम्न जातियां और जोड़ी गयी :–

1. कुथलिया बोरा
2. घृत चाहत बाहंग
3. रवाल्टा
4. गोर्खा समुदाय

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0
एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. स्थाई पता – ग्राम/मो.....

   तहसील.....विकासखण्ड.....जनपद.....
4. जाति.....उपजाति.....

   (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. मासिक/वार्षिक आय.....(वहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र)
6. स्थाई निवा प्रमाण पत्र.....(राशिनकार्ड, मतदाता सूची, बिजली का बिल आदि संलग्न करें)
7. जन्मतिथि.....(ग्राम पंचायत/नगर पालिका या विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म आयु का प्रमाण पत्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो)
8. शैक्षणिक तथा तकनीकी पृष्ठभूमि/कार्यानुभव यदि कोई हो.....
9. प्रस्ताव योजना का नाम.....लागत.....स्थाई/कार्यस्थल.....

   (परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें)
10. वर्तमान गतिविधियां.....
11. जमानतदारों के नाम व पता (सम्पत्ति का विवरण संलग्न करें, यदि किसी विभाग/संस्था में सेवारत हों तो विभाग का नाम पद व पता स्पष्ट लिखें)

    अ. ..... ब. .....

    ....
12. क्या पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता (ऋण/अनुदान) प्राप्त किया था?

    हां/नहीं, यदि हां तो विवरण दें :–

    विवरण.....विभाग का नाम.....प्राप्त सहायता .....

    वसूली की स्थिति.....
13. पूर्व में प्राप्त ऋण के अंश की वसूली की अद्यावधिक स्थिति अथवा इसी उद्देश्य हेतु विकास खण्ड/जनपद/राज्य के किसी वित्तीय संस्थान/विभाग/अन्य श्रोत से ऋण/अनुदान प्राप्त नहीं किया है न ही बकायेदार हूं। (रु0 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाय)।

    प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य पूर्णतः सही एवं वास्तविकता पर आधारित हैं तथा जो प्रमाण पत्र संलग्न किये जा रहे हैं वह सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त है। यदि कोई तथ्य सत्यता से परे पाया जाता है या छुपाया जाता है तो उसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा।

स्थान :–

दिनांक :– आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :– प्रार्थना पत्र के समस्त कालम स्वच्छ भाषा में भरे होने चाहिए, अपूर्ण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(2)

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

लाभार्थी श्री/श्रीमती/कु0.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी.....का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक.....को प्राप्त हुआ। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये तथ्यों की जांच कर ली गई है एवं संलग्न प्रपत्रों की प्रमाणिकता की पुष्टि कर ली गई है, जो सही पायी गई है। निगम के अभिलेखों की पुष्टि के उपरांत यह प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी द्वारा इससे पूर्व कोई ऋण/अनुदान किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया हैं लाभार्थी पात्रता के अन्तर्गत है। अतः प्रस्तुत योजना.....जो आर्थिक दृष्टि से परिपुष्ट है, की लागत रु0.....मानते हुए राष्ट्रीय निगम का ऋण.....प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण..... प्रतिशत अनुदान.....एवं लाभार्थी अंश के रूप में.....की स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

बहुउद्देशीय कर्मी/सहायक समाज कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी
(पदनाम मुहर सहित)

सहायक प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी पदने जिला प्रबन्धक
(पदनाम मुहर सहित)

(राज्य स्तरीय चयन समिति के प्रयोगार्थ)

जनपद स्तरीय ऋण स्वीकृति समिति के संस्तुति के आधार पर श्री/श्रीमती/कु.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....को राष्ट्रीय

.....वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना.....

की लागत रु.....मानते हुए.....मियादी ऋण.....

प्रतिशत ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण.....4 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुदान रु.....

एवं रु.....लाभार्थी अंश के रूप में मानते हुए स्वीकृत किया जाता है।

उप महाप्रबन्धक
(योजना प्रभारी)

महा प्रबन्धक

प्रबन्ध निदेशक

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि.

द्वारा संचालित योजनाओं से वित्त पोषण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

योजना का नाम : जनपद :

बैंक का नाम जिसमें आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है :–

.....

पासपोर्ट आकार का नवीनतम छायाचित्र

1. आवेदक का नाम.....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम.....
3. आवेदक का पूरा स्थाई पता.....

.....

4. आवेदक की जाति.....ण्ण्ण्ण्.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. आवेदक की वार्षिक आय.....(समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त)
6. राशन कार्ड की उपलब्धता.....(छाया प्रति संलग्न करें)
7. यदि ड्राईविंग लीईसेन्स कामर्शियल या अन्य कोई प्रशिक्षण पत्र की आवश्यकता हो तो उसका विवरण

.....(छाया प्रति संलग्न करें)

8. योजना जिसके अधीन लाभार्थी लाभ चाहता है.....

(जैसे स्वतः रोजगार योजना/स्वच्छकार विमुक्ति योजना/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम से वित्त पोषित आदि)

9. योजना के अधीन परियोजना का विवरण.....

.....

10. परियोजना की अनुमानित लागत.....(शब्दों में).....

.....(परियोजना रिपोर्ट/वित्तीय सहायता रिपोर्ट संलग्न की जा सकती है।)

11. क्या पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किया था (विवरण लिखें).....

.....

12. पूर्व में प्राप्त लाभ के ऋण अंश के वसूली.....की अध्यावधिक स्थिति

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य पूर्णतया सही एवं वास्तविकता पर आधारित हैं यदि कोई तथ्य सत्यता से परे पाया जाता है तब मैं उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा।

स्थान :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

चयनित/सर्वेक्षित संख्या.....वर्ष.....

एस.सी.पी. 1 क्रमांक संख्या.....बैंक प्रेषण की तिथि.....

उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक.....को प्राप्त हुआ है तथा कार्यालय से उपलब्ध लाभार्थी पंजी/एस.सी.पी.–1 के पृष्ठ संख्या.....पर दर्ज कर लिया गया। उक्त आवेदन पत्र स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है। चयन समिति द्वारा संस्तुत योजना की लागत (शहरी क्षेत्र के मामलों में)

रुपये.....योजना की लागत.....

बैंक ऋण.....मा. मनीऋण.....अनुदान.....

ग्राम वि.अ./स.वि.अ./खण्ड विकास अधिकारी/सहा. प्रबन्धक/जिला प्रबन्धक

दिनांक.....(पदनाम मोहर सहित)

(बैंक के प्रयोग हेतु)

श्री/श्रीमती/कु.....निवासी.....

.....की योजना.....हेतु

रु.....(शब्दों में).....

का बैंक ऋण.....प्रतिशत ब्याज दर पर दिनांक.....को स्वीकृत किया जाता है इस ऋण अदायगी.....मासिक/त्रैमासिक किस्तों में की जायेगी।

स्वीकृत योजना की लागत रु. .....मानते हुए बैंक ऋण.....

तथा निगम द्वारा मा. मनी ऋण रु.....एवं रु.....शासकीय अनुदान अवमुक्त की जाये।

बैंक शाखा प्रबन्धक के मुहर सहित हस्ताक्षर

दिनांक.....

(जिला समन्वय समिति का चयन का विवरण)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लाभार्थी का चयन समिति की बैठक दिनांक.....

में किया गया है जिसका कार्यवृत्त कार्यालय में सुरक्षित है इस प्रकरण में रु.....

अनुदान रु.....मा. मनी ऋण तथा रु.....बैंक ऋण/अनुविनि ऋण स्वीकृत कर भुगतान किया गया।

जिला प्रबन्धक

ब.उ.वि.वि. निगम

मैनुअल

13

खण्ड–13

(निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल)

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की स्थिति

(Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by.)

विकलांगजनों को उत्तरांचल परिवहन निगम लि0 की बसों में निशुल्क यात्रा हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाभ दिया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र पर अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर आयुक्त विकलांगजन कार्यालय से निर्गत परिचय पत्र/पासबुक के आधार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

यात्रा सुविधा केवल उन्हीं विकलांगों को दये होगी जो निम्नांकित श्रेणियों मे से किसी एक में आते हों :–

(1) जो पूर्ण रूप से अंधे हों या अल्पदृष्टि (लो विजन) हों निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागदीरी) अधिनियम 1995 में उपबंधित परिभाषा के अनुसार)

(2) जो पूर्ण रूप से मूक हों, बधिर हों या दोनों हों (निःशक्त व्यक्ति (समाज अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में उपबंधित परिभाषा के अनुसार

(3) जिनके एक हाथ व एक पैर या जिनके दोनों हाथ या पैर पूर्ण रूप से कटे हों।

(4) जिनके एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हो।

(5) जो मानसिक रूप से मंद/रूग्ण हों (आटिज्म' प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में उपबंधित परिभाषा के अनुसार)

(6) जो लेप्रोसी मुक्त विकलांग हों।

उपरोक्त विकलांगता हेतु उल्लिखित श्रेणी (6) को छोड़कर शेष पांच श्रेणियों के विकलांगजनों के एक सहयोगी को विकलांगजन की ही भांति निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। विकलांग व्यक्ति एवं अनुमन्य सहवर्ती को यात्रा हेतु निर्धारित अतिरिक्त कर (यात्रीकर) एवं मार्ग में पड़ने वाले अन्य करों का भुगतान यात्रा के समय बस परिचालक को करना होगा। (शासनादेश संलग्न)

"उत्तरांचल परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों के लिए यात्रा नियम, 2006"

1. संक्षिप्त नाम

इन नियमों का संक्षिप्त नाम "उत्तरांचल परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों के लिए यात्रा नियम, 2006" है।

2. प्रारम्भ

ये नियम विकलांगजनों के कल्याणार्थ तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। इन नियमों के प्रभावी होने पर पूर्ववर्तीराज्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित सभी नियमावलियां उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में निष्प्रभावी हो जाएंगी। इसके अन्तर्गत उत्तरांचल परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

3. परिभाषा

इन नियमों अन्तर्गत, जब तक विषय के संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,

(क) 'निगम' से उत्तरांचल परिवहन निगम अभिप्रेत है।

(ख) 'बस' से निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर संचालित की जाने वाली साधारण बसें अभिप्रेत हैं, और इसमें हाईटैक, डीलक्स, सेमीडीलक्स, वायुशीतित शयनयान, वातानुकूलित (वोल्वो) तथा वीडियो बस सम्मिलित नहीं हैं

(ग) 'राज्य' से उत्तरांचल राज्य अभिप्रेत है, और

(घ) 'आयुक्त' से विकलांगजन आयुक्त, उत्तरांचल अभिप्रेत हैं

4. विकलांगजनों को उत्तरांचल राज्य में निःशुल्क यात्रा सुविधा निगम की बसों में भिक्षावृत्ति से भिन्न प्रयोजन के लिए यात्रा करने पर दी जाएगी।

5. विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा मात्र साधारण श्रेणी की बसों में अनुमन्य होगी। हाईटैक, डीलक्स, सेमीडीलक्स, वायुशीतित शयनयान, वातानुकूलित (वोल्वो) तथा वीडिया बसों पर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

6. यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व विकलांग व्यक्ति, बस के परिचालक को आयुक्त कार्यालय से निर्गत परिचय पत्र/पासबुक अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

7. निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रमाणत्र जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कितने विकलांग व्यक्तियों ने एक त्रैमास में निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपयोग किया, के साथ मांग पत्र दिए जाने पर अनुमन्य धनराशि आयुक्त द्वारा निगत को उपलब्ध कराई जाएगी।

8. (1) यात्रा की सुविधा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र पर तथा/अथवा मुख्य चिकित्साधकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर आयुक्त द्वारा निर्गत परिचयपत्र/पासबुक के आधार पर दी जाएगी।

(2) यात्रा सुविधा केवल उन्हीं विकलांगों को देय होगी जो निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक में आते हों :–

(क) जो पूर्ण रूप से अंधे हों या अल्पदृष्टि (लो विजन) हों (निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में उपबंधित परिभाषा के अनुसार)।

(ख) जो पूर्ण रूप से मूक हों, बधिर हों या दोनों हों (निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में उपबंधित परिभाषा के अनुसार)।

(ग) जिनके एक हाथ व एक पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों।

(घ) जिनके एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों।

(च) जो मानसिक रूप से मंद/रुग्ण हों (आर्टिजन, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में उपबंधित परिभाषा के अनुसार)।

(छ) जो लेप्रोसी मुक्त विकलांग हों।

9. पूर्वोक्त नियम 8(2) में विकलांगता हेतु उल्लिखित श्रेणी (छ) को छोड़कर शेष पांच श्रेणियों के विकलांगजनों एक सहयोगी को विकलांगजन की ही भांति निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। विकलांग व्यक्ति एवं अनुमन्य सहवर्ती को यात्रा हेतु निर्धारित अतिरिक्त कर (यात्रीकर) एवं मार्ग में पड़ने वाले अन्य करों का भुगतान यात्रा के समय बस के परिचालक को करना होगा।

10. परिवहन निगम की बसों में विकलांग को पूरे वित्तीय वर्ष में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।

11. नगर बस सेवा में भी यह सेवा अनुमन्य होगी, यदि उत्तरांचल सड़क परिवहन निगम नगर सेवा संचालित करते हों।

12. पूर्वोक्त नियम 8(2) के अन्तर्गत उल्लिखित विकलांगों को निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

13. निगम को विकलांगों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित विभाग के आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के अनुसार पारस्परिक सहमति से धनराशि का भुगतान आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

14. विकलांगजन द्वारा स्वयं अथवा सहवर्ती सहित यात्रा करने पर निगम की बस का परिचालक, विकलांगजन को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र एवं आयुक्त द्वारा निर्गत परिचय पत्र/पासबुक देखने के पश्चात, संबंधित विकलांगजन को सहवर्ती सहित गन्तव्य स्थान तक यात्रा सुविधा उपलब्ध करायेगा। साथ ही इस बस यात्रा सुविधा को विकलांगजन के पास उपलब्ध पासबुक में सहवर्ती के नाम सहित दर्ज भी कर देगा तथा विकलांगजन की पासबुक की संख्या व पासबुक के जिस पेज पर यात्रा दर्ज की गई है, उसकी संख्या अपने मार्गपत्र में विकलांगजन व सहवर्ती के नाम एवं यात्रा कहां से कहां तक की गई, की प्रविष्टि सहित अंकित करेगा। इस यात्रा का लेखा–जोखा डिपो कार्यालय में मार्गपत्र चेकिंग लिपिक द्वारा अलग पंजिका में रखा जायेगा।

15. जिला समाज कल्याण अधिकारी एक पंजिका रखेंगे जिसमें ऐसे विकलांगों का उल्लेख होगा जो निगम की बसों में यात्रा करने हेतु पात्र हैं।

16. इस नियमावली में संशोधन समाज कल्याण विभाग, वित्त विभाग एवं उत्तरांचल परिवहन निगम की सहमति से ही किया जाएगा।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

उत्तरांचल शासन

समाज कल्याण अनुभाग–2

संख्या 12/XVII(1)2/2006-06(18)/2004

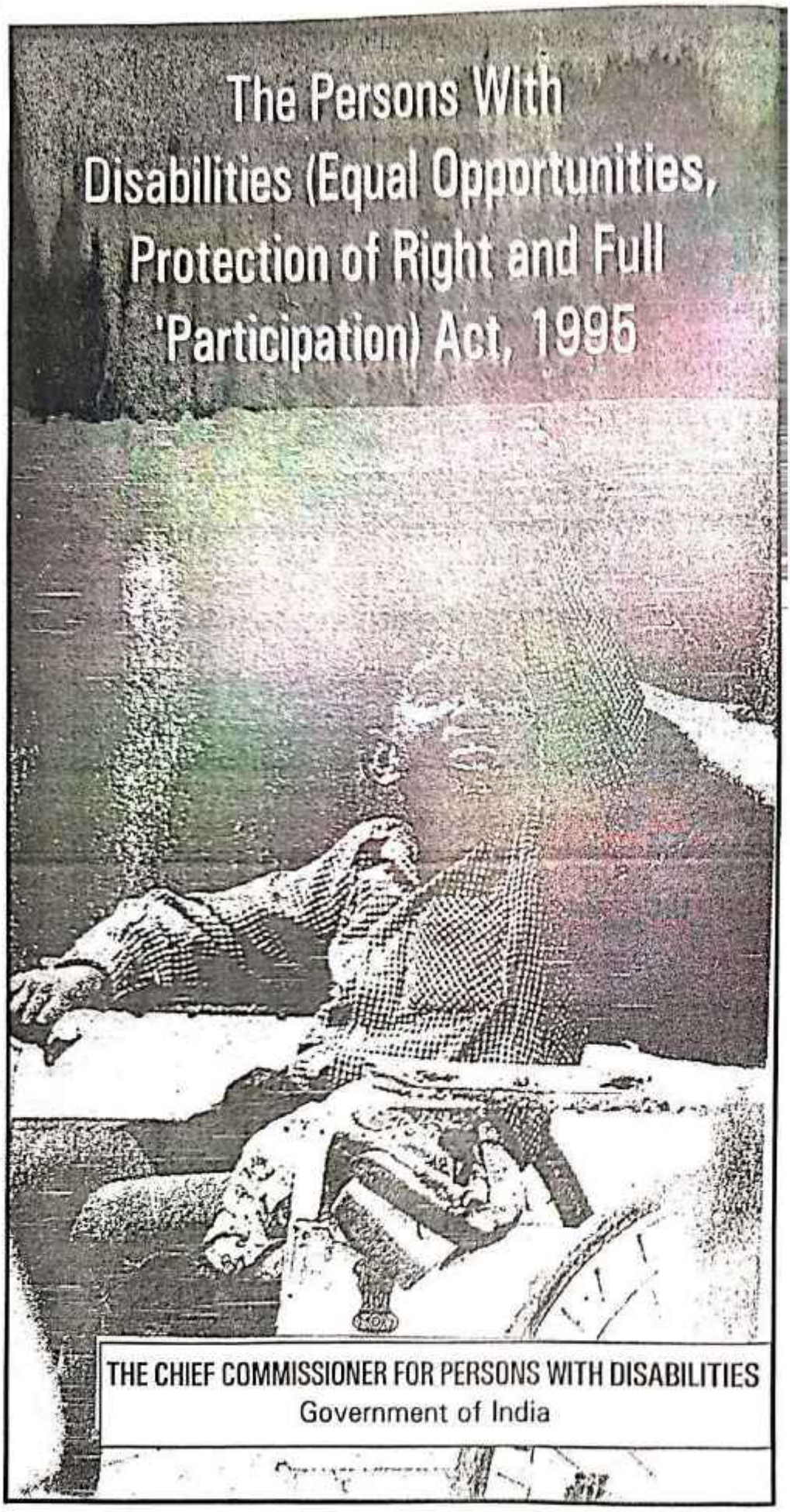
देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. मुख्य आयुक्त, विकलांग जन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, 31, सैक्टर–39, नोएडा (उ. प्र)
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
10. विकलांगजन आयुक्त, उत्तरांख्ल, देहरादून।
11. प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल परिवहन निगम, देहरादून।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि कृपया इस नियमावली की 200 प्रतियां मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
14. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उपसचिव।


The Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Full 'Participation) Act, 1995
THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
Government of India

This brochure aims to provide information on the salient features of the Persons with Disabilities Act, 1995.

PURPOSE OF THE ACT

This Act was pased by the Parliament on Dec. 12, 1995 and notified on Feb, 7, 1996. The Act elaborates the responsibility of the Central and State governments, local bodies to provide services, facilities and equal opportunities to people with disabilities for participating as productive citizens of the country. The Act enlists the rights and facilities persons with disabilities would be entitled to and which are enforceable.

this is an important landmark. The Act provides for both preventive and promotional aspects of rehabilitation.

CHAPTER 1 : PRELIMINARY

The Disabilities covered in the Act are :- blindness, low vision, leprosycured, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation, and mental illness.

A person with disability has to be certified by a medical authority that he or she is suffering from not less than 40% of the disability.

CHAPTER II - THE CENTRAL CO-OPERATION COMMITTEE AND EXECUTIVE COMMITTEE

1. The Central Government shall constitute a Central Co-ordination Committee (CCC), headed by the Minister of Social Justice & Empowerment.

   The CCC consists of 39 persons, 24 are official members and 15 nominated by the Government, will represent NGOs and associations concerned with disabilities. At least one woman and one person from SC or ST is to be included. The term of all the members will be for three years.

   The important functions of the Central Co-ordination Committee are :

   a) Review and coordinate the activities of Government and NGOs.

   b) Development of National Policy.

   c) Advise the Central Government on the formulation of policies, programmes, legislation and projects.

   d) Advocacy with national and international organisations with a view to provide for schemes and projects for the disabled in the national and international plans and programmes.

e) Review donor funding policies from the perspective of their impact on persons with disabilities.

f) To ensure barrier-free environment.

g) Monitor and evaluate the impact of policies and programmes.

The Central Co-ordination Committee will be bound by such directions in writing as the Central Government may give it.

The Committee shall meet once every six months.

2. The Central Executive Committee (CEC)

the Central Executive Committee shall carry out the dicisions of the Central Co-ordination Committee. the Executive Committee shall meet every three months. The CEC will consist of 23 persons, including five persons concerned with disability.

CHAPTER----------

Each state shall appoint a State Coordination Committee, consisting of 23 official and five non-official members.

The State Executive Committee will have 13 official and 5 non-official members.

The terms and conditions and functions of the State Committees shall be the same as those of the Central Committee.

CHAPTER IV : PREVENTION AND EARLY DETECTION OF DISABILITIES

Within the limits of acconomic capacity and development, the concerned authorities, with a view to preventing the occurrence of disabilities, shall-

a) Undertake or cause to be undertaken surveys, investigations and research concerning the cause of occurrence of disabilities.

b) Promote various methods of preventing disabilities.

c) Screen all children at least once in a year for identifying at-risk cases.

d) Provide facilities to trained staff at the primary health centres.

e) Sponsor or cause to be sponsored, awareness campaigns and dissemibate information for general hygiene, health and sanitation.

f) Take measures for prenatal and postnatal care of mother and child.

g) Educate the public through the pre-schools, schools, primary health centres, village level workers and anganwadi workers.

h) Create awareness amongist masses through TV, radio and other mass media on the causes of disabilities and its prevention.

CHAPTER V - EDUCATION

The Act envisages :

- Every child with disability should hve access to free and adequate education till the age of 18. Students with disabilities should be integrated into normal schools. Special schools should be established in government and private sectors and equipped with vacational training facilities.
- Introduce scheme for non formal education of chileren who have discontinued their education after 5the class. Conduct special part time classes for functional literacy in the age group of 16 and above and provide each child, free of cost, special books and equipment needed for his or her education, including education in open schools and universities.
- The Government shall set up teachers training institutions to run special scholls and integrated schools for children with disabilities by trained teachers.
- The Government shall provide, to such children, transport facilities, remove architectural barriers from educational institutions imparting vacational training and education, provide books, uniforms and other materials to children attending schools, grant scholarships and restructure curriculum for the beriefit of students with disabilities.
- Government shall promote research for assistive device to give a child with disability equal opportunities in education.
- Government shall present a comprehensive education scheme including transportation, barrier-free environment and grievances redressal forum severe disabilities. The Government shall establish and maintain institutors for them. Where private institutions, meating Government standards exist, they shall be recognised for the purpose.

CHAPTER XII - THE CHIEF COMMISSIONER AND COMMISSING FOR PERSONS WITH DISABILITIES

The Central Government shall appoint a chief Commissioner for persons with Disabilities for the implementation of this Act. The Chief Commissioner shall coordinate the work of the Commissioners

and monitor the utilization of funds distributed by the Central Government.

Commissioners shall have similar responsibilities at the State level. the chief Commissioner and the Commissioners shall take up any complaint or suomoto regarding deprivation of rights of persons with disabilities and non-implementation of laws, rules, orders, instructions issued by the Government or local authorities.

The chief Commissioner and Commissioners have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil procedure, 1908 for summoning and enforcing attendance of witnesses, receiving evidence on affaidavits, etc.

The chief Commissioner shall prepare an annual report to be layed in Parliament. The Commissioners shall submit an annual report to the respective State Legislature.

CHAPTER XIII - SOCIAL SECURITY

The Government shall, within their economic limits, undertake rehabilitation of all persons with disabilities and grant financial assistance to NGOs undertaking rehabilitatin programmes for persons with disabilities. There possible, give unemployment allowance to persons with disabilities registered with the special employment exchange for more than 2 years, and who could not be placed in any gainful occupation, Insurance schemes for the employed, and if needed, insurance scheme for non-employed by the Government is also mentioned.

CHAPTER XIV - MISCELLANEOUS

Whoever attempts to commit fraud and avail of the benefits meant for persons with disabilities shall be punished upto two years imprisonment or upto Rs. 20,000/- fine or both.

The Chief Commissioner, the Commissioners, officers and staff provided to implement this Act shall be deemed to be public servants.

Note : Please refer to authentic copy of the Act for legal purposes and details

You are welcome to contact :

The Chief Commissioner For Persons With Disabilities,
Govt. of India, New Delhi.
E-mail : ccduma@rediff.com
Web site : www. ccdisabilities.org
G-31, Sector-39, NOIDA (U.P.)-201301
Tel. : 91-4500282
The Commissioner (Disabilities), Respective States,

CHAPTER VI - EMPLOYMENT

A) The Government shall reserve atleast 3% posts in Govt. jobs for persons with disabilities as follows :-

1. Blindness or low vision	1%
2. Hearing Impairment	1%
3. Locomotor Disability or Cerebral palsy	1%

If in any year, the vacancy cannot be fillect then it would be carried to next year, thereafter people with other disabilities can be given employment and finally, if there is no suitable disabled person, then only a person other than a person with disability can be given employment.

B) Special employment exchanges would be set up.

C) Appropriate Governments shall formulate schemes for ensuring employment of persons will disabilities including training.

D) All Government educational institutions and those receiving aid from the Government shall reserve not less than 3% seats for persons with disabilities. Not less than 3% of all poverty alleviation schemes shall be reserved for persons with disabilities. government shall within their economic capacities frame scheme to give incentives to employers in public and private sectors to ensure that atleast 5% of their work force is composed of persons with disabilities.

CHAPTER VII - AFFIRMATIVE ACTION

The Government shall provide aids and appliances to persons with disabilities and shall provide land at concessional rates for allotment to persons with disabilities for housing, business, special recreation centres, special schools, research centres and factories by entrepreneurs with disabilities.

CHAPTER VIII - NON DISCRIMINATION

A) Govt. transport shall take special measures to adapt theirfacilities and amenities so to permit easy access to persons with disabilities.

B) All authorities shall within their capacity, provide auditory signals along red lights, crossings, Constructions shall be designed for wheel chair users and engraving on zebra crossing for blind people. Buildings and toilets shall be constructed with ramps and other features.

C) No employer shall terminate an employee who acquires a disability during service. No employer shall also deny promotion to an employee on grounds of disability.

CHAPTER IX - RESEARCH AND MANPOWER DEVELOPMENT

Government shall promote and sponsor research to prevent disability, rehabilitate the disabled, develop assistive device, identify jobs and develop pro-disabled structural features in factories and offices.

CHAPTER X - RECOGNITION OF INSTITUTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Within six months of this Act being passed, persons running establishments or institutions for persons with disabilities shall apply under the Act, for a certificate of registration from a competent authority of the State Government.

CHAPTER XI INSTITUTION FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES

Persons having 80% or more disabilities are considered persons with

सं० डी० एल० – 33004 / 96

REGISTERED No. DL-33004/96

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II – खण्ड–I

PART II - Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1996 / पौषण 11,1917

New Delhi, Monday, Jaunary 1, 1996/Pausa 11,1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 1st January, 1996/Pause 11,1917 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 1st January, 1996, and is hereby published for general information :-

THE PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION), ACT, 1995

No. 1 of 1996

(1st January, 1996)

An Act to give effect to the Proclamation on the Full Participation and Equality of the People with Disabilities in the Asian and Pacific Region.

Whereas the Meeting to Launch the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons 1993&2000 convened by the Economic and social Commission for Asia and Pacific held at Beijing on 1st to 5the December, 1992, adopted the Proclamation on the full Participation and Equality of People with Disabilities in teh Asian and Pacific Region :

And Whereas India is a signatory to the said Proclamation;

And whereas it is considered necessary to implement the Proclamation aforesaid.

Be it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. *(1)* This Act may be called the Persons With Disabilities (Equal Opportunities,. Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

(2) It extends to the whole if India except the State of Jannu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "appropriate Government" means, -

(i) in relation to the Central Government or any establishment/holly or substantially financed by that Government, or a Cantonment Board constituted under the Cantonment Act, 1924, the Central Government;

2 of 1924

(ii) in relation to a State Government or any establishment wholly or substantially financed by that Government, or any local authority other than a Cantonment Board, the State Government;

(iii) in respect of the Central Coordination Committee and the Central Executive Committee, the Central Government;

(iv) in respect of the State Coordination Committee and the State Executive Committee, the State Government;

(b) "blindness" refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely :-

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse;

(c) " Central Coordination Committee" means the Central Committee constituted under sub-section (1) of section 3;

(d) "Central Executive Committee" means the Central Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 9;

(e) "Cerebral palsy" means a group of non-progressive conditions of a person characterised by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development;

(f) "Chief Commissioner" means the Chief Commissioner appointed under sub-section (I) of section 57;

(g) "Commissioner" means the Commissioner appointed under sub-section (1) of section 60;

(h) "Competent authority" means the authority appointed under section 50;

(i) "disability" means-

(i) blindness;

(ii) low vision;

(iii) leprosy - cured;

(iv) hearing impairment;

(v) locomotor disability;

(vi) mental retardation;

(vii) mental illness;

(j) "employes" means,-

(i) in relation to a Government, the authority notified by the Head of the Department in this behalf or where no such authority is notified, the Head of the Department; and

(ii) in relation to an establishment, the Chief Executive Officer of that establishment;

(k) "Establishment" means a corporation established by or-under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a local authority or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 and includes Departments of a government;

1 of 1956

(l) "hearing impairment" means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies;

(m) "institution for persons with disabilities" means an institution for the reception, care, protection, education, training, rehabilitation or any other service of persons with disabilities;

(n) "leprosy cured person" means any person who has been cured of leprosy but is suffering from-

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him from undertaking any gainful occupation, and the expression "Leprosy Cured" shall be construed accordingly;

(o) "locomotor disability" means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy;

(p) "medical authority" means any hospital or institution specified for the purposes of this Act by notification by the appropriate Government;

(q) "mental illness" means any mental disorder other than mental retardation;

(r) "mental illness" means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person which is specially characterised by subnormality of intelligence;

(s) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(t) "person with disability" means a person suffering from not less than forty percent of any disability as certified by a medical authority;

(u) "person with low vision" means a person with impairment of visual functioning even after treatment of standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device;

(v) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(w) "rehabilitation" refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychiatric or social functional levels;

(x) "Special Employment Exchange" means any office or place established and maintained by the Government for the collection and furnishing of information, either by keeping of registers or otherwise, respecting-

(i) persons who seek to engage employees from amongst the persons suffering from disabilities;

(ii) persons with disability who seek employment;

(iii) vacancies to which person with disability seeking employment may be appointed;

(y) "State Executive Committee" means the State Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 13;

(z) "State Executive Committee" means the State Executive Committee constituted under sub-section (1) section 19.

CHAPTER II

THE CENTRAL COORDINATION COMMITTEE

Central Coordination Committee.

3. (1) The Central Government shall by notification constitute a body to be known as the Central Coordination Committee to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it, under this Act.

(2) The Central Coordination Committee shall consist of-

(a) the Minister in charge of the Department of Welfare in the Central Government, chairperson, ex officio;

(b) the Minister of State in -Charge of the Department of Welfare in the Central government, Vice-Chairperson, ex officio;

(c) Secretaries to the Government of India in-charge of the Department of Welfare, Education, Woman and child Development, Expenditure, Personnel, Training and Public Grievances, Health, Rural Development, industrial Development, Urban Affairs and Employment, Science and Technology, Legal Affairs, Public enterprises, Members, *ex officio;*

(d) Chief Commissioner, Member, ex officio;

(e) chairman Railway Board, Member, ex officio;

(f) Director - General of labour, Exployment and Training, Member, ex officio;

(g) Director, National Council for Educational Research and Training, Member, *ex officio;*

(h) three Members of Parliament, of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States, Members;

(i) three persons to be nominated by the Central Government ot represent the interests, which in the opinion of that Government ought to be represented, Members;

(j) Directors of the-

(i) national Institute for the Visually Handicapped, Dehradun;

(ii) National Institute for the Mentally Handicapped, Secundrabed;

(iii) national Institute for the Orthopedically Handicapped, Calcutta;

(iv) Ali Yavar Jung National Institute for the hearing Handicapped, Mumbai; Members, *ex officio;*

(k) four Members to be nominated by the Central Government by rotation to represent the States and the Union Territories in such manner as may be prescribed by the Central Government.

Provided that no appointment under this clause shall be made except on the recommendation of the State Government or, as the case may be, the Union Territory;

(l) five persons as far as practicable, being persons with disabilities, to represent non-governmental organisations or associations which are concerned with disabilities, to be nominated by the Central Government, one from each area of disability, Members :

Provided that while nominting persons under this clause, the Central Government shall nominate at least one woman and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(m) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Welfare dealing with the welfare of the handicapped, Member - Secretary, ex officio;

(3) The office of the Member of the Central Coordination Committee shall not disqualify its holder for being chosen as or for being a Member of either House of Parliament.

Term of office of Members.

4. (1) Save as otherwise provided by or under this Act a Member of Central Coordination Committee nominated under clause (i) or clause (l) of sub-section (2) of section 3 shall hold office for a term of three years from the date of his nomination;

Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his terms, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) The term of office of an ex officio Member shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was so nominated.

(3) The Central government may if it thinks fit remove any Member nominated under clause (i) or clause (l) of sub-section (2) of section 3, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(4) A Member nominated under clause (i) or clause (l) of sub-section (2) of section 3 may at any time resign his office by writing under his hand, addressed to the Central government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant.

(5) A casual vacancy in the Central Coordination Committee shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Member in whose place he was so nominated.

(6) A member nominated under clause (i) of sub-section (2) of section 3 shall receive such allowances as may be prescribed by the Central Government.

(7) Members nominated under clause (i) and clause (l) of sub-section (2) of section 3 shall receive such allowances as may be prescribed by the Central Government.

Disqualifi cations

5. (1) No person shall be a Member of the Central Coordination Committee, who-

(a) is, or at any tijme has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent, court, or

(c) is or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central government, involves moral turpitude, or

(d) is or at any time has been convicted of an ofence under this Act, or

(e) has so abused in the opinion of the Central Government his position as a Member as to render his continuance in the Central Coordination Committee detrimental to the interests of the general public.

(2) No order of removal shall be made by the Central Government under this section unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) Not withstanding anything contained in sub-section (l) or sub-section (6) of section 4, a Member who has been removed under this section shall not be, eligible for renomination as a Member.

Vacation of seems by Members.

6. If a Member of the Central Coordination Committee becomes subject to any of the disqualifications specified in section 5, his seat shall become vacant.

Meetings of the Central Coordination Committee.

7. The Central Coordination Committeeshall meet at least once in every six months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed by the Central Government.

Functions of the Central Coordination Committee.

8. (1) Subject to the provisions of this Act, the function of the Central Coordination Committee shall be to serve as the national focal point on disability matters and facilitate the continuous evolution of a comprehensive policy towards solving the problems faced by persons with disabilities.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the Central Coordination Committee may perform all or any of the following functions, namely :-

(a) review and coordinate the activities of all the Departments of Government and other Governmental and non-Governmental Organisations which are dealing with matters relating to persons with disabilities.

(b) develop a national policy to address issues faced by persons with disabilities :

(c) advise the Central Government on the formulation of policies, programmes, legislation and projects with respect to disability;

(d) take up the cause of persons with disabilities with the concerned authorities and the international organisations with a view to provide for schemes and projects for the disabled in the national plans and other programmes and policies evolved by the international agencies;

(e) review in consultation with the donor agencies their funding policies from the perspective of their impact on persons with disabilities;

(f) take such other steps to ensure barrier free environment in public places, work places, public utilities, schools and other institutions;

(g) monitor and evaluate the impact of policies and programmes designed for achieving equality and full paricipation of persons with disabilities;

(h) to perform such other functions as may be prescribed by the Central Government.

Central Executive Committee.

9. (1) The Central Government shall constitute a Committee to be known as the Central Executive Committee to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Central Executive Committee shall consist of-

(a) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Welfare, Chair person, ex officio;

(b) the Chief Commissioner, Member, ex officio;

(c) the Director-Central for Health Services, Member, ex officio.

(d) the Director-General, Employment and Training, Member, ex officio.

(e) six persons not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India to represent the Ministries or Departments of Rural Development, Education, Welfare, Personnel Public Grievances and Pension, Urban affairs and Employment, Science and Technology, Members, ex officio;0000000000

(f) the Financial Advisor, Ministry of Welfare in the Central Government, Members, ex officio;

(g) Advisor (Rarif) Railway Board, Member, ex officio;

(h) four members to be nominated by the Central Government, by rotation, to represent the State Governments and the Union Territories in such manner as may be prescribed by the Central government;

(i) one person to be nominated by the Central Government to represent the interest, which in the opinion of the Central government ought to be represented, Member,

(j) five persons, as far as practicable, being persons with disabilities, to repre sent non-governmental organisation or associations which are concerned with disabili ties, to be nominated by the Central Government, one from each area of disability, Members.

Provided that while nominating persons under this clause, the Central Gov ernment shall nominate at least one woman and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(k) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Welfare dealing with the welfare of the handicapped, Member - Secretary, ex officio.

(3) Members nominated under clause (i) and clause (j) of sub-section (2) shall receive such allowances as may be prescribed by the Central government;

Functions of the Central Executive Committee.

(4) A Member nominated under clause (i) or clause (l) of sub-section (2) of section 3 may at any time resign his office by writing under his hand, addressed to the Central government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant.

Meetings of the Central Executive Committee.

10. (1) The Central Executive Committee shall be the executive body of the Central Coordination Committee and shall be responsible for carrying out the decisions of the Central Coordination Committee.

(2) Without prejuduce to the provisions of sub-section (1), the Central Executive Committee shall also perform such other functions as may be delegated to it by the Central Coordination Committee.

Temporary association of persons with Central Executive Committee for particular purposes.

11. The Central Executive Committee shall meet at least once in three months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed by the Central government.

12. (1) the Central Executive Committee may associate with itself in such manner and for such purposes as may be prescribed by the Central Government any person whose assistance or advice it may desire to obtain in performing any of its functions under this Act.

(2) A person associated with the Central Executive Committee under sub-section (l) for any purpose shall have the right to take part in the discussions of the Central Executive Committee relevant to that purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the said Committee, and shall not be member for any other purpose.

(3) A person associated with the said Committee under sub-section (1) for any purpose shall be paid such fees*and allowances, for attending its meetings and for attending to any other work of the said Committee, as may be prescribed by the Central Government.

CHAPTER III

THE STATE COORDINATION COMMITTEE

State Coordination Committee.

13. (1) Every State Government shall, by notification, constitute a body to be known as the State Coordination Committee to exercise the powers conferred on, and to perform the function assigned to it, under this Act.

(2) the State Coordination Committee shall consist of-

(a) The Minister in charge of the Department of Social Welfare in the State Government, Chairperson, ex officio;

(b) the Minister of State in -charge of the Department of Social Welfare, if any Vice-Chairperson, ex officio;

(c) Secretaries to the State Government in-charge of the Departments of Welfare, Education, Woman and Child Development, Expenditure, Personnel Training and Public Grievances, Health, Rural Development, Industrial Development, Urban Affairs and Employment, Science and Technology, Public Enterprises, by whatever name called, Members, ex officio;

(d) Secretary of any other Department which the State Government considers necessary, Members, ex officio;

(e) Chairman Bureau of Public Enterprises (by whatever name called) Member, ex officio;

(f) five persons, as far as practicable, being persons with disabilities, to represent non-governmental organisations or associations which are concerned with disabilities, to be nominated by the State Government, one from each area of disability, Members;

Provided that while nominating persons under this clause, the State Government shall nominate at least one women and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(g) three Members of State Legislature, of whom two shall be elected by the Legislative Assembly and one by the Legislative Councul, if any;

(h) three persons to be nominated by the State Government to represent agriculture, industry or trade or any other interest, which in the opinion of State Government ought to be represented, Members, ex officio;

(i) the Commissioner, Member, ex officio;

(j) Secretary to the State Government dealing with the welfare of the handicapped, Member - Secretary, ex officio;

(3) Notwithstanding anything contained in this section, no State Coordination Committee shall be constituted for a Union Territory and in relation to a Union Territory, the State Coordination Committee shall exercise the functions and perform the functions of a State Coordination Committee for the Union Territory;

Provided that in relation to a Union Territory, the State Coordination Committee may delegate all or any of its powers and functions as under this sub-section to such person or body of persons as the Central Government may specify.

14. (1) Save as otherwise provided by or under this Act a Member of Central Coordination Committee nominated under clause (f) or clause (h) of sub-section (2) of section 13 shall hold office for a term of three years from the date of his nomination;

Terms and conditions of service of Members.

Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his terms, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) The term of office of an ex officio Member shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was so nominated.

(3) The State Government may if it thinks fit remove any Member nomi nated under clause (f) or clause (h) of sub-section (2) of section 13, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(4) A Member nominated under clause (f) or clause (h) of sub-section (2) of section 13 may at any time resign his office by writing under his hand, addressed to the State Government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant.

(5) A casual vacancy in the State Coordination Committee shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Member in whose place he was so nominated.

(6) A member nominated under clause (f) of sub-section (2) of section 13 shall receive such allowances as may be prescribed by the State Government.

Disqualifications

(7) Members nominated under clause (f) and clause (h) of sub-section (2) of section 13 shall receive such allowances as may be prescribed by the State Government.

15. (1) No person shall be a Member of the State Coordination Committee, who-

(a) is, or at any tijme has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent, court, or

(c) is or has been convicted of an offence which, in the opinion of theState Government, involves moral turpitude, or

(d) is or at any time has been convicted of an ofence under this Act, or

(e) has so abused in the opinion of the State Government his position as a Member as to render his continuance in the State Coordination Committee detrimental to the interests of the general public.

(2) No order of removal shall be made by the State Government under this section unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) Not withstanding anything contained in sub-section (l) or sub-section (6) of section 14, a Member who has been removed under this section shall not be, eligible for renomination as a Member.

16. If a Member of the State Coordination Committee becomes subject to any of the disqualifications specified in section 15, his seat shall become vacant.

Vacation of seats.

17. The State Coordination Committee shall meet at least once in every six months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed.

Meetings of theState Coordination Committee.

Functions of the State Coordination Committee.

18. (1) Subject to the provisions of this Act, the function of the State Coordination Committee shall be to serve as the national focal point on disability matters and facilitate the continuous evolution of a comprehensive policy towards solving the problems faced by persons with disabilities.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the State Coordination Committee may, within the State perform all or any of the following functions, namely :-

(a) review and coordinate the activities of all the Departments of Government and other Governmental and non-Governmental Organisations which are dealing with matters relating to persons with disabilities.

(b) develop a State policy to address issues faced by persons with disabilities :

(c) advise the State Government on the formulation of policies, programmes, legislation and projects with respect to disability;

(d) review in consultation with the donor agencies their funding policies from the perspective of their impact on persons with disabilities;

(e) take such other steps to ensure barrier free environment in public places, work places, public utilities, schools and other institutions;

Provided that while nominating persons under this clause, the State Govern ment shall nominate at least one woman and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(f) monitor and evaluate the impact of policies and programmes designed for achieving equality and full paricipation of persons with disabilities;

State Executive Committee.

(h) to perform such other functions as may be prescribed by the State Govern ment.

19. (1) The State Government shall, constitute a Committee to be known as the State Executive Committee to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The State Executive Committee shall consist of-

(a) the Secretary Department of Welfare, Chairperson, ex officio;

(b) the Commissioner, Member, ex officio;

(c) nine persons not below the rank of a Joint Secretary to the State Govern ment, to represent the Departments of Health, Finance, Rural Development, Educa tion, Welfare, Personnel Public Grievances and Pension, Urban affairs and Employ ment, Science and Technology, Members, ex officio;

(d) one person to be nominated by the State Government to represent the in terest, which in the opinion of the State Government ought to be represented, Member.

(e) five persons, as far as practicable being persons with disabilities, to repre sent non-governmental organisation or associations which are concerned with disabili ties, to be nominated by the State Government, one from each area of disability, Members.

Provided that while nominating persons under this clause, the State Govern ment shall nominate at least one woman and one person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(f) Joint Secretary dealing with thedisability division in the Department of Welfare, Member-Secretary, ex officio.

(3) Members nominated under clause (d) and clause (e) of sub-section (2) shall receive such allowances as may be prescribed by the State government;

(4) A Member nominated under clause (d) or clause (e) may at any time resign his office by writing under his hand, addressed to the State government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant.

Functions of the State Executive Committee.

20. (1) The State Executive Committee shall be the executive body of the State Coordination Committee and shall be responsible for carrying out the decisions of the Central Coordination Committee.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Central Executive Committee shall also perform such other functions as may be delegated to it by the State Coordination Committee.

Meetings of the State Executive Committee.

21. The State Executive Committee shall meet at least once in three months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed by the State Government.

Temporary association of persons with State Executive Committee for particular purposes.

22. (1) The State Executive Committee may associate with itself in such manner and for such purposes as may be prescribed by the State Government any person whose assistance or advice it may desire to obtain in performing any of its functions under this Act.

(2) A person associated with the State Executive Committee under sub-section (1) for any purpose shall have the right to take part in the discussions of the State Executive Committee relevant to that purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the said Committee, and shall not be member for any other purpose.

(3) A person associated with the said Committee under sub-section (1) for any purpose shall be paid such fees and allowances, for attending its meetings and for attending to any other work of the said Committee, as may be prescribed by the State Government.

Power to give directions

23. In the performance of its functions under this Act-

(a) the Central Coordination Committee shall be bound by such directions in writing, as the Central Government may give to it; and

(b) the State Coordination Committee shall be bound by such directions in writing, as the Central Coordination Committee or the State Government may give to it;

Provided that where a direction given by the State Government is inconsistent with any direction given by the Central Coordination Committee, the matter shall be referred to the Central Government for its decision.

Vacancies not to invalidate proceedings

24. No act or proceeding of the Central Coordination Committee, the Central Executive Committee, a State Coordination Committee or a State Executive Committee shall be called in question on the ground merely on the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of such Committees;

CHAPTER IV

Prevention and Early Detection of Disabilities

Appropriate Governments and local authorities to take certain steps for the prevention of occurrence of disabilities.

25. Within the limits of their economic capacity and development, the appropriate Governments and the local authorities, with a view to preventing the occurrence of disabilities, shall-

(a) undertake or cause to be undertaken surveys, investigations and research concerning the cause of occurrence of disabilities.

(b) promote various methods of preventing disabilities;

(c) screen all the children at least once in a year for the purpose of identifying "atrisk" cases;

(d) provide facilities for training to the staff at the primary health centres;

(e) sponsor or cause to be sponsored awareness campaigns and disseminate or cause to be disseminated information for general hygiene, health and sanitation;

(f) take measures for pre-natal, perinatal and post-natal care of mother and child;

(g) educate the public through the pre-schools, schools, primary health centres, village level workers and anganwadi workers;

(h) create awareness amongst the masses through television, radio and other mass media on the causes of disabilities and the preventive measures to be adopted;

CHAPTER V

Education

Appropriate Governments and local authorities to provide children with disabilities free education etc.

26. the appropriate Governments and the local authorities shall-

(a) ensure that every child with a disability has access to free education in an appropriate environment till the attains the age of eighteen years;

(b) endeavour to promote the integration of students with disabilities in the normal schools;

(c) promote setting up of special schools in Government and private sector for those in need of special education, in such a manner that children with disabilities living in any part of the country have access to such schools;

Appropriate Governments and local authorities to make schemes and programmes for non-formal education etc.

(d) endeavour to equip the special schools for children with disabilities with vocational training facilities;

27. the appropriate Governments and the local authorities shall by notification make schemes for-

(a) conducting part-time classes in prespect of children with disabilities who having completed education up to class fifth and could not continue their studies on a whole-time basis;

(b) conducting special part-time classes for providing functional literacy for children in the age group of sixteen and above;

(c) imparting non-formal education by utilizing the available manpower in rural areas after giving them appropriate orientation;

Research for designing and developing new assistive devices, teaching aids etc.

(d) imparting education through open schools or open universities;

(e) conducting class and discussions through interactive electronic or other media;

(f) providing every child with disability, free of cost special books and equipment needed for his education.

28. The appropriate Government shall initiate or cause to be initiated research by official and non-governmental agencies for the purpose of designing and developing new assistive devices, teaching aids, special teaching material or such other items as are necessary to give a child with disability equal opportunities in education.

Appropriate Governments to set up, teachers training institution to develop trained manpower for schools for children with disabilities.

Appropriate Governments to set up, teachers training institutions to develop trained manpowere for schools for children with disabilities.

29. The appropriate Governments shall set up adequate number of teachers' training institutions and assist the national institutes and other voluntary organisations to develop teachers' training programmes specialising in disabilities so that requisite trained manpower is available for special schools and integrated schools for children with disabilities.

30. Without prjueice to the foregoing provisions, the appropriate Governments shall by notification prepare a comprehensive education scheme which shall make provision for- Appropriate Governments to prepare a comprehensive education scheme providingfor transport facilities, supply of books etc.

(a) transport facilities to the children with disabilities or in the alternative fi nancial incentives to parents to guardians to enable their children with disabilities to attend schools;

(b) the removal of architectural barriers from schools, colleges or other insti tutions imparting vacational and professional training;

(c) the supply of books, uniforms and other materials to children with disabili ties attending school;

(d) the grant of scholarship to students with disabilities;

(e) setting up of appropriate fora for the redressal of grievances of parents regarding the placement of their children with disabilities;

(f) suitable modification in the examination system to eliminate purely math ematical questions for the benefit of blind students and students with low vision;

(g) restructuring of curriculum for the benefit of children with disabilities;

(h) restructuring the curriculum for benefit of students with hearing impair ment to facilitate them to take only one language as part of their curriculum.

31. All educational institutions shall provide or cause to be provide amanuensis to blind students and students with or low vision Educational institutions to provide amanuensis to students with visual handicap.

CHAPTER VI

Employment\

Identification of posts which can be reserved for persons with disabilities

32. Appropriate Governments shall-

(a) identify posts in the establishments which can be reserved for the persons with disability;

(b) at periodical intervals not exceeding three years, review the list of posts identified and up date the list taking into consideration the developments in technology.

33. Every appropriate Government shall appoint in every establishment such percent- Reservation of posts age of vacancies not less than three per cent. for persons or class of persons with disability of which one per cent each shall be reserved for persons suffering from-

(i) blindness or low vision;

(ii) hearing impairment;

(iii) locomotor disability or cerebral palsy, in the posts identified for each disability.

Provided, that the appropriate Government may, having regard to the type of work car- ried on in any department or establishment, by notification subject to such conditions, if any, as may be specified in suchnotification, exempt any establishment from the provisions of this section.

Special Employement Exchange

34. (1) The appropriate Government may, by notification, require that from such date as may be specified, by notification, the employer in every establishment shall furnish such information or return as may be prescribed in relation to vacancies appointed for persons with disability that have occured or are about to occur in that establishment to such Special Employment Exchange as may be prescribed and the establishment shall thereupon comply with such requisition.

(2) The form in which and the intervals of time for which information or returns shall be furnished and the particulars, they shall contain shall be such as may be prescribed.

Power to inspect record or document in possession of any establishment.

Power to inspect record or document in possession of any establishment

35. Any person authorised by the Special Employment Exchange in writing, shall have access to any relevant record or document in the possession of any establishment and may enter at any reasonable time and premises where he believes such record or document to be, and inspect or take copies of relevant records or documents or ask any question necessary for obtaining any information.

Vacancies not filled up to be carried forward

36. Where in any recruitment year any vacancy under Section 33, cannot be filled up due to non-availability of a suitable person with disability or, for any other sufficient reason, such vacancy shall be carried forward in the succeeding recruitment year and if in the succeeding recruitment year also suitable person with disability is not available, it may first be filled by ineerchange among the three categories and only when there is no person with disability available for the post in that year, the employer shall fill up the vacancy by appointment of a person, other than a person with disability.

Provided that if the nature of vacancies in an establishment is such that a given category of person can not be employed, the vacancies may be interchanged among the three categories with the prior approval of the appropriate Government.

Employer to maintain records

37. (1) Every employer shall maintain shcuh record in relation to the person with disability employed in his establishment in such form and in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.

(2) The records maintained under sub-section (1) shall be open to inspection at all reasonable hours by such persons as may be authorised in this behalf by general or special order by the appropriate Government.

Schemes for ensuring employment of persons with disabilities.

Schemes for ensuring employement of persons with disabilities

38. (1) The appropriate Governments and local authorities shall by notification formulate schemes for ensuring employment of persons with disabilities, and such schemes may provide for-

(a) the training and welfare of persons with disabilities;

(b) the relaxation of upper age limit;

(c) regulating the employment;

(d) health and safety measures and creation of a non-handicapping environment in places where persons with disabilities are employed;

(e) the manner in which and the persons by whom the cost of operating the schemes is to be defrayed; and

(f) constituting the authority responsible for the administration of the scheme.

All educational institutions to reserve seats for persons with disabilities

39. All Government educational institutions and other educational institutions receiving aid from the Government, shall reserve not less than three per cent. seats for persons with disabilities.

Vacancies to be reserved in poverty alleviation schemes

40. The appropriate Governments and local authorities shall reserve not less than three per cent in all poverty alleviation schemes for the benefit of persons with disabilities.

Incentives to employers to ensure five percent of the work force is composed of persons with disabilities.

41. The appropriate Governments and the local authorities shall, within the limits of their economic capacity and development, provide incentives to employers both in public and private sectors to ensure that at least five per cent of their work force is composed of persons with disabilities.

Incentives to employers to ensure five percent of the work force is composed of persons with disabilities

CHAPTER VII

Affirmative Action

42. The appropriate Governments shall be botification make schemes to provide aids and appliances to persons with disabilities.

Aids and appliances to persons with disabilities

43. The appropriate Governments and local authorities shall by notification frame schemes in favour of persons with disabilities, for the preferential allotment of land at concessional rates for-

Schemes for perfential allotment of land for certain purposes.

(a) house;

(b) setting up business;

(c) setting up of special recreation centres;

(d) establishment of special schools;

(e) establishment of research centres;

(f) establishment of factories by entreprencurs with disabilities.

CHAPTER VIII

Non-discrimination

44. Establishments in the transport sector shall, within the limits of their economic capacity and development for the benefit of persons with disabilities, take special measures to-

Non-discrimination in transport.

(a) adapt rail compartments, buses, vessels and aircrafts in such a way as to permit easy access to such persons;

(b) adapt foilets in rail compartments, vessels, aircrafts and waiting rooms in such a way as to permit the wheel chair users to use them conveniently.

45. The appropriate Governments and the local authorities shall, within the limits of their economic capacity and development, provide for-

Non-discrimination in the road.

(a) installation of auditory signals at red lights in the public roads for the benefit of persons with visually handicap;

(b) causing curb cuts and slopes tobe made in pavements for the easy access of wheel chair users;

(c) engraving on the surface of the zebra crossing for the blind or for persons with low vision;

(d) engraving on the edges of railway platform for the blind or for persons with low vision;

(e) devising appropriate symbols of disability;

(f) warning signals at appropriate places.

Non-discrimination in the built environment

46. The appropriate Governments and the local authorities shall, within the limits of their economic capacity and development, provide for-

(a) ramps in public buildings;

(b) adaptation of toilets for wheel chair users;

(c) braille symbols and auditory signals in elevators or lifts;

(d) ramps in hospitals, primary health centres and other medical care and re habilitation institutions;

Non-discrimination in Government employment

47. (1) No establishment shall dispense with, or reduce in rank, an employee who acquires a disability during his service;

Provided that, if an employee, after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, could be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits; Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation. whichever is earlier.

(2) No promotion shall be denied to a person merely on the ground of his disability; Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any establishment, by notification and subject to such conditions, if any, as may be specified in such notification, exempt any establishment from the provisions of this section.

CHAPTER IX

Research and Manpower Development

Research

48. The appropriate Governments and local authorities shall promote and sponsor research, inter alia, in the following areas-

(a) prevention of disability;

(b) rehabilitation including community based rehabilitation;

(c) development of assistive devices including their psycho-social aspects;

(d) job identification;

(e) on site modification in offices and factories;

Financial incentives to Universities to enable them to undertake research

49. The appropriate Governments shall provide financial assistance to universities, other institutions of higher learning, professional bodies and non-governmental research units or institutions, for undertaking research for special education, rehabilitation and manpower development.

CHAPTER X

Recognition of Institutions for Persons with Disabilities

Complete authority

50. The State Government shall appoint any authority as it deems fit to be a competent authority for the purposes of this Act.

No person to establish or maintain an institution for persons with disabilities except in accordance with a certificate of registration.

51. Save as otherwise provided under this Act, no person shall establish or maintain any institution for persons with disabilities except under and in accordance with a certificate of registration issued in this behalf by the competent authority :

Provided that a person maintaining an institution for persons with disabilities immediately before the commencement of this Act may continue to maintain such institution for a period of six months from such commencement and if he has made an application for

such certificate under this section within the said period of six months, till the disposal of such application.

Certificate of registration

52. (1) Every application for a certificate of registration shall be made to the competent authority in such form and in such manner as may be prescribed by the State Government.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), and competent authority shall make such enquiries as it may deem fit and where it is satisfied that the applicant has complied with the requirements of this Act and the rules made thereunder it shall grant a certificate of registration to the applicant and where it is not so satisfied the competent authority shall, by order, refuse to grant the certificate applied for :

Provided that before making any order refusing to grant a certificate thw competent authority shall give to the applicant a reasonable opportunity of being heard and every order of refusal to grant a certificate shall be communicated to the applicant in such manner as may be prescribed by the State Government.

(3) No certificate of registration shall be granted under sub-section (2) unless the institution with respect to which an application has been made is in a position to provide such facilities and maintain such standards as may be prescribed by the State Government.

(4) A certificate of registration granted under this section,-

(a) shall, unless revoked under section 53, remain in force for such period as may be prescribed by the State Government.

(b) may be renewed from time to time for a like period; and

(c) shall be in such form and shall be subject to such conditions as may be prescribed by the State Government.

(5) An application for renewal of a certificate of registration shall be made not less than sixty days before the period of validity.

(6) The certificate of registration shall be displayed by the institution in a conspicuous place.

Revocation of certificate

53. (1) the competent authority may, if it has reasobalbe cause to believe that the holder of the certificate of registration granted under sub-section (2) of section 52 has-

(a) make a statement in relation to any application for the issue or renewal of the certificate which is incorrect or false in material particulars; or

(b) committed or has caused to be committed any breach of rules or any con ditions subject to which the certificate was granted, it may, after making such inquiry, as it deems fit, by order, revoke the certificate :

Provided that no such order shall be made until an opportunity is given to the holder of the certificate to show cause as to why the certificate should not be revoked.

(2) Where a certificate in respect of an Institution has been revoked under sub-section (1), such institution shall cease to function from the date of such revocation:

Provided that where an appeal lies under section 54 against the order of revocation, such institution shall cease to function-

(a) where no appeal has been preferred immediately on the expiry of the pe riod prescribed for the filling of such appeal, or

(b) where such appeal has been preferred, but the order of revocation has been upheld, from the date of the order of appeal.

(3) On the revocation of a certificate in respect of an institution, the competent authority may direct that any person with disability who is an immate of such institution on the date of such revocation, shall be-

(a) restored to the custody of her or his parent, spouse or lawful guardian, as the case may be, or

(b) transferred to any other institution specified by the competent authority.

(4) Every institution which holds a certificate of registration which is revoked under this section shall, immediately after such revocation, surrender such certificate to the competent authority.

Appeal

54. (1) Any person aggrieved by the order of the competent authority refusing to grant a certificate or revoking a certificate may, with in such period as may be prescribed by the State Government, prefer an appeal to that Government against such refusal or revocation.

(2) The order of the State Government on such appeal shall be final.

Act not to apply to institutions established or maintained by the Central or State Government.

Act not to apply to institutions established or maintained by the Central or State Government

55. Nothing contained in this Chapter shall apply to an institution for persons with disabilities established or maintained by the Central Government or a State Government.

CHAPTER XI

Institution for Persons with Service Disabilities

Institutions for persons with svere disabilities

56. The appropriate Government may establish and maintain Institutions for persons with severe disabilities at such places as it thinks fit.

(2) Where the appropriate Government is of opinion that any institution other than an institution, established under sub-section (1), is fit for the rehabilitation of the persons with severe disabilities, the Government may recognise such institution as an institution for persons with severe disabilities for the purposes of this Act :

Provided that no institution shall be recognised under this section unless such institution has complied with the requirements of this Act and the rules made thereunder.

(3) Every institution established under sub-section (1) shall be maintained in such manner and satisfy such conditions as may be prescribed by the appropriate Government.

(4) For the purposes of this section "person with severe disability" means a person with eighty per cent or more of one or more disabilities.

CHAPTER XII

The Chief Commissioner and Commissioners for persons with disabilities

Appointment of Chief Commissioner or persons with disabilities

57. (1) The Central Government may, by notification, appoint a Chief Commissioner for persons with disabilities for the purposes of this Act.

(2) A person shall not be qualified for appointment as the Chief Commissioner unless he has special knowledge or practical experience in respect of matters relating to rehabilitation.

(3) The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Chief Commissioner shall be such as may be prescribed by the Central Government.

(4) The Central government shall determine the nature and categories of officers and other employees required to assist the Chief Commissioner in the discharge of his functions and provide the Chief Commissioner with such officers and other employees as it thinks fit.

(5) The officers and employees provided to the Chief Commissioner shall discharge their functions under the general superintendence of the Chief Commissioner. Functions of the Chief Commissioner.

(6) The salaries and allowances and other conditions of service of officers and employees provided to the Chief Commissioner shall be such as may be prescribed by the Central Government.

58. The Chief Commissioner shall-

(a) coordinate the work of the Commissioners;

(b) monitor the utilisation of funds disbursed by the Central Government;

(c) take steps to safeguard the rights and facilities made available to persons with disabilities;

(d) submit reports to the Central Government on the implementation of the Act at such intervals as that Government may prescribe.

59. Without prejudice to the provisions of section 58 the Chief Commissioner may of his own motion or on the application of any aggrieved person or otherwise look into complaints with respect to matters relating to- Chief Commissioner to look into complaints with respect to deprivation of rights of persons with disabilities

(a) deprivation of rights of persons with disabilities;

(b) non-implementation of laws, rules, bye-laws, regulations, executive orders, guidelines or instructions made or issued by the appropriate Governments and the local authorities for the welfare and protection of rights or persons with disabilities, and take up the matter with the appropriate authorities.

60. (1) Every State Government may, be notification appoint a Commissioner for persons with disabilities for the purpose of this Act. Appointment of Commissioners for persons with disabilities

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Commissioner unless he has special knowledge or practical experience in respect of matters relating to rehabilitation.

(3) The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Commissioner shall be such as may be prescribed by the State Government.

(4) The State Government shall determine the nature and categories of officers and other employees required to assist the Commissioner in the discharge of his functions and provide the Commissioner with such officers and other employees as it thinks fit.

(5) The officers and employees provided to the Commissioner shall discharge their functions under the general superintendence of the Commissioner.

(6) The salaries and allowances and other conditions of service of officers and employees provided to the Commissioner shall be such as may be prescribed by the State Government.
Powers of the Commissioner.

61. The Commissioner within the State shall- Powers of the Commissioner.

(a) coordinate with the departments of the State Government for the programmes and schemes for the benefit of persons with disabilities;

(b) monitor the utilisation of funds disbursed by the State Government;

(c) take steps to safeguard the rights and facilities made available to persons with disabilities;

(d) submit reports to the State Government on the implementation of the Act at such intervals as that Government may prescribe and forward a copy thereof to the Chief Commissioner.

Commissioner to look into complaints with respect to matters relating to deprivation of rights of persons with disabilities

62. Without prejudice to the provisions of section 61 the Commissioner may of his own motion or on the application of any aggrieved person or otherwise look into complaints with respect to matters relating to-

(a) deprivation of rights of persons with disabilities;

(b) non-implementation of laws, rules, bye-laws, regulations, executive orders, guidelines or instructions made or issued by the appropriate Governments and the local authorities for the welfare and protection of rights or persons with disabilities, and take up the matter with the appropriate authorities.

Authorities and officers to have certain powers of civil court

63- (1) The Chief Commissioner and the Commissioners shall, for the purpose of discharging their functions under this Act, have the same powers as are vested in a court under the Code of Civel Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of the following matters, namely :- 5 of 1908

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requisitioning any public record or copy thereof from any court of office;

(d) receiving evidence on affidavits. and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

(2) Every proceeding before the Chief Commissioner and Commissioners shall be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Chief Commissioner, the Commissioner, the competent authority, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973. 45 of 1860 2 of 1974

Annual report to be prepared by the Chief Commissioner.

64. (1) The Chief Commissioner shall prepare in such form and at such time for each financial year as may be prescribed by the Central Government an annual report giving a full account of his activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Central Government.

(2) The Central Government shall cause the annual report to be laid before each House of Parliament along with the recommendations explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendation made therein so far as they relate to the Central Government and the reasons for non-acceptance, if any, of any such recommendation or part.

Annual reports to be prepared by the Commissioners.

Annual reports to be prepared by the Commissioners.

65. (1) The Commissioner shall prepare in such form and at such time for each financial year as may be prescribed by the State Government an annual report giving a full account of his activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

(2) The State Government shall cause the annual report to be laid before each State Legislature along with the recommendations explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendation made therein in so far as they relate to the State Government and the reasons for non-acceptance, if any, of any such recommendation or part.

CHAPTER XIII

Social Security

Appropriate Governments and local authorities to undertake rehabilitation.

61. (1) The appropriate Governments and the local authorities shall, within the limits of their economic capacity and development, undertake and cause to be undertaken rrehabilitation of all persons with disabilities.

(2) For purpose of sub-section (1), the appropriate Governments and local authorities shall grant financial assistance to non-governmental organisations.

(3) The appropriate Governments and the local authorities while formulating rehabilitation policies shall consult the non-governmental organisations working for the cause of persons with disabilities.

Insurance scheme for employees with disabilities

67. (1) the appropriate Government shall be notification frame an insurance scheme for the benefit of its employees with disabilities.

(2) Notwithsatnding anything contained in this section, the appropriate Government may instead of framing an Insurance scheme frame an alternative security scheme for its employees with disabilities.

Unemployment allowance

68. the appropriate Governments shall within the limits of their economic capacity and development shall by notification frame a scheme for payment of an unemployment allowance to person with disabilities registered with the Special Employment Exchange for more than two years and who could not be placed in any gainful occupation.

CHAPTER XIV

Miscellaneous

Punishment for fradulently availing any benefit meant for persons with disabilities

69. Whoever, fraudulently avails or attempts to avail, any benefit meant for persons with disabilities, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to twenty thousand rupees or with both.

Chief Commissioners, Commissioner, officer and other staff to be public servants

70. The Chief Commissioner, the Commissioners and other officers and staff provided to them shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

45 of 1860

Protection of action taken in good faith

71. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government, the State Governments or the local authority or any officer of the Government in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act and any rules or orders made thereunder.

Act to be in addition to and not in derogationof any other law.

72. The provisions of this Act, or the rules made thereunder shall be in addition to, and not in derogation of any other law for the time being in force or any rules, order or any instructions issued thereunder, enacted or issued for the benefit of persons with disabilities.

Powers of appropriate Government to make rules.

Power of appropriate Government to make rules.

73. (1) The appropriate Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and iwthout prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the manner in which a State Government or a Union territory shall be chosen under clause (k) of sub-section (2) of section 3;

(b) allowances which members shall receive under sub-section (7) of section 4;

(c) rules of procedure which the Central Coordination Committee shall ob serve in regard to the transaction of business in its meetings under section 7;

(d) such other functions which the Central Coordination Committee may per form under clause (h) of sub-section (2) of section 8;

(e) the manner in which a State Government or a Union territory shall be chosen under clause (h) of sub-section (2) of section 9;

(f) allowances which members shall receive under sub-section (3) of section 9;

(g) rules of procedure which the Central Executive Committee shall observe in regard to the transaction of business in its meetings under section 11;

(h) the manner and purposes for which a person may be assiciated under sub section (1) of section 12;

(i) fee and allowances which a person associated with the Central Executive Committee shall receive under sub-section (3) of section 12;

(j) allowances which members shall receive under sub-section (7) of section 14;

(k) rules of procedure which the State Executive Committee shall observe in regard to the transaction of business in its meetings under section 17;

(l) such other functions which the State Coordination Committee may per form under clause (g) of sub-section (2) of section 18;

(m) allowances which members shall receive under sub-section (3) of section 19;

(n) rules of procedure which a State Executive Committee shall observe in regard to the transaction of business at its meetings under section 21;

(o) the manner and purposes for which a person may be assiciated under sub section (1) of section 22;

(p) fee and allowances which a person associated with the State Executive Committee may receive under sub-section (3) of section 22;

(q) information or return which the employer in every establishment should furnish and the Special Employment Exchange to which such information or return shall be furnished under sub-section (1) of section 34;

(r) the form and the manner in which record shall be maintained by an em ployer under sub-section (1) of section 37;

(s) the form and manner in which an application shall be made under sub-section (1) of section 52;

(t) the manner in which an order of refusal shall be communicated under sub-section (2) of section 52;

(u) facilities or standards required to be provided or maintained under sub-section (3) of section 52;

(v) the period for which a certificate of registration shall be valid under clause (a) of sub-section (4) of section 52;

(w) the form in which and conditions subject to which a certificate of registra tion shall be granted under clause (c) or the sub-section (4) of section 52;

(x) period within which an appeal shall lie under sub-section (1) of section 54;

(y) the manner in which an institution for persons with severe disabilities shall be maintained and conditions which have to be satisfied under sub-section (3) of section 56;

(z) the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chief Commissioner under sub-section (3) of section 57;

(za) the salary, allowances and other conditions of service of the Chief Com missioner under sub-section (3) of section 57;

(zb) intervals at which the Chief Commissioner shall report to the Central Government under clause (d) of section 58;

(zc) the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Commissioner under sub-section (3) of section 60;

(zd) the salary, allowances and other conditions of service of officers and employees under sub-section (6) of section 60;

(ze) intervals within which the Commissioner shall report to the State Gov ernment under clause (d) of section 61;

(zf) the form and time in which annual report shall be prepared under sub-section (1) of section 64;

(zg) the form and time in which annual report shall be prepared under sub-section (1) of section 65;

(zh) any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every notification made by the Central Government under the provision to section 33, proviso to sub-section (2) of section 47, every scheme framed by it under section 27, section 30, sub-section (1) of section 38, section 42, section 43, section 67, section 68 and every rule made by it under sub-section (1), shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule, notification or scheme, both houses agree that the rule, notification or scheme should not be made, the rule, notification or scheme shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule, notification or scheme, as the case may be.

(4) Every notification made by the State Government under the provisio to section 33, proviso to sub-section (2) of section 47, every scheme made by it under section 27, section 30, sub-section (1) of section 38, section 42, section 43, section 67, section 68 and every rule made by it under sub-section (1), shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature, where it consists of two Houses or where such legislature consists of one House before that House.

74. In section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, for clause (d), the following clause shall be substituted namely :-

(d) a person with disability as defined in clause (i) of section 2 of the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

K.L. Mohanpuria
Secy., to the Govt. of India.

मैनुअल

14

खण्ड–14

(निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल)

इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो :–

(Details in respect of the information, available to or held by it reduced in an electronic form.)

इस संबंध में उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल का पॉर्टल **www.uttara.in** में विभागीय योजनाओं एवं क्रियाकलापों की बैबसाइड उपलब्ध है। इसकी अतिरिक्त उत्तरांचल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा विभागीय आंकड़ो एव योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्य कामेट टैक्नोलाजी प्रा. लि. देहरादून द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। संस्था द्वारा विभागीय आंकड़ो के कम्प्यूटरीकरण का कार्य जनपद स्तर पर पूर्ण कर लिया गया है एवं शीघ्र ही निदेशालय स्तर पर अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर लिया जायेगा।

सूचनाओं के प्राप्ति एवं प्रेषण हेतु मुख्यालय स्तर पर इन्टरनेट की स्थापना की गई है, इन्टरनेट आईडी **directorsw@sancharnet.in** है एवं सभी जनपदीय कार्यालयों में इन्टरनेट की स्थापना की जा रही है। विभाग सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम् तकनीक को उपयोग में लिये जाने हेतु प्रतिबद्व है ताकि विभागीय क्रियाकलापों की सूचना जन–जन तक पहुँच सके।

मैनुअल

15

खण्ड–15

(निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागारिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्ठियां, जिनके अर्न्तगत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुराक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है :–

(The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library of reading room, if maintained for public use.)

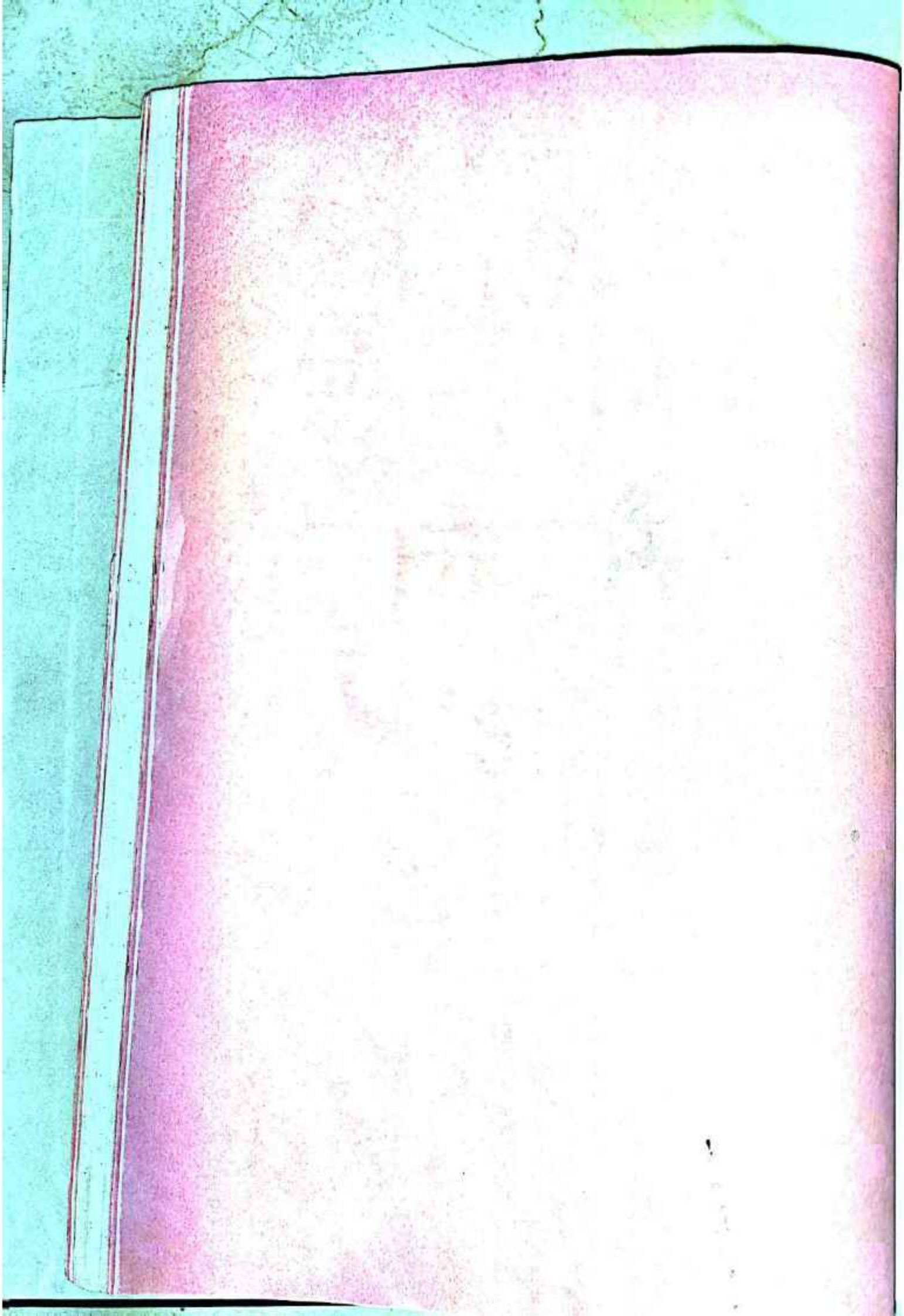
प्रत्येक जनपद एवं निदेशालय में एक वाचनालय कक्ष स्थापित किया जायेगा जिसमें विभाग से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध रहेगी. निदेशालय स्तर पर समस्त अभिलेख/विशिष्टियों का अवलोकन करने की व्यवस्था है जिसे कोई भी व्यक्ति अवलोकित कर सकता है ।

जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में यह व्यवस्था की गयी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम का सूचना पट सभी लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय में नागरिकों की सुविधा के लिए लगाया गया है। नागरिक जन कार्यालय अवधि में 10.00 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं तक विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभिलेख, मैनुवल आदि अवलोकन कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। यदि इस संबंध में उन्हें परामर्श की आवश्यकता हो तो, आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

मैनुअल

16



खण्ड–16

(निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्ठियां :–

(The names, designations and other particulars of the public information officers.)

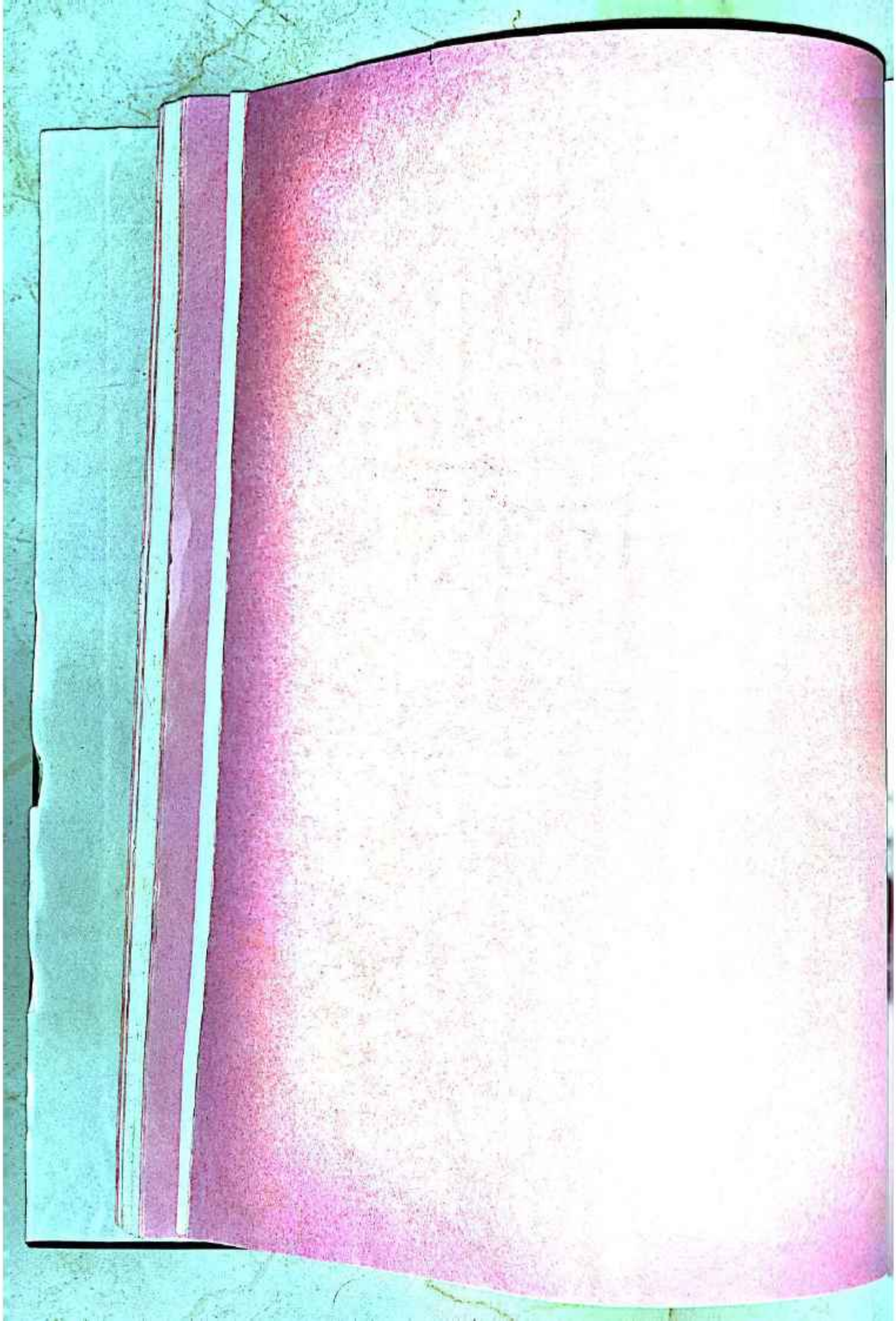
निदेशालय स्तर पर श्री आर.पी. पंत, सहायक निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

पदनाम	पता	दूरभाष न.
मुख्यालय स्तर		
सहायक निदेशक /लोक सूचना अधिकारी	समाज कल्याण निदेशालय, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल	05946–282819 05946–282233
पदनाम	**पता**	**दूरभाष न.**
जिला स्तर		
1. जिला समाज कल्याण अधिकारी/, लोक सूचना अधिकारी	4 रेस्टकैम्प, हरिद्वार रोड़, देहरादून	0135–2628099
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी,/ लोक सूचना अधिकारी	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार	01334–239743
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार	01334–239743
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	टिहरी	01378–227236
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	पौड़ी	01368–222375
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	चमोली	01377–252216
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	उत्तरकाशी	01374–223731
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी	चम्पावत	05965–230307
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	रूद्रप्रयाग	01364–233528
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	विकास भवन, भीमताल–नैनीताल	05942–248431
10. जिला समाज कल्याण अधिकारी	विकास भवन, अल्मोडा	05962–235564
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	ऊधमसिंह नगर	05944–242593
12. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	पिथौरागढ़	05964–227475
13. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	बागेश्वर	05963–221334, 221011

मैनुअल

17



खण्ड–17

(निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल)

अन्य सूचना, जो विहित की जाय

(Such other information as may be prescribed .)

निदेशालय का निजी भवन नहीं है. किराये के भवन में संचालित है. भवन निर्माण हेतु भूमि के चयन/क्रय की कार्यवाही की जायेगी.

विभाग का नाम : समाज कल्याण, उत्तरांचल

प्रशासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0नं0/ई–मेल
निदेशालय/ विभागाध्यक्ष (अ) मुख्यालय	सहायक निदेशक	समाज कल्याण, उत्तरांचल, कालाढुँगी रोड, हल्द्वानी–नैनीताल	फोन. 05946–282813 फोन. 05946–282233 1.directorsw@sancharnet.in 2.directorswu@sancharnet.in 3.sunildahundiyal@yahoo.com

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी	4 रेस्टकैम्प, हरिद्वार रोड़, देहरादून	0135–2628099
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी,	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार	01334–239743
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार	01334–239743
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी,	टिहरी	01378–227236
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी	पौड़ी	01368–222375
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	चमोली	01377–252216
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी	उत्तरकाशी	01374–223731
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी	चम्पावत	05965–230307
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी	रूद्रप्रयाग	01364–233528
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी	विकास भवन, भीमताल–नैनीताल	05942–248431
10. जिला समाज कल्याण अधिकारी	विकास भवन, अल्मोडा	05962–235564
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी	ऊधमसिंह नगर	05944–242593
12. जिला समाज कल्याण अधिकारी	पिथौरागढ़	05964–227475
13. जिला समाज कल्याण अधिकारी	बागेश्वर	05963–221334, 221011

सब–डिवीजन/तहसील/विकासखण्ड/अन्य निम्न स्तर पर सूचना के अधिकारी अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण (शासन/निदेशालय के लिए)

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद–पौड़ी)

क्र. सं.	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन/ ई.. मेल
1.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, पौडी	222543
2.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, कल्जीखाल	220034
3.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, खिर्सू	228523
4.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, कोट	229006
5.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, पावौ	224018
6.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, थैलीसैण	225791
7.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, बीरौखाल	223687
8.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, पोखड़ा	265626
9.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, ऐकेश्वर	265312
10.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीडॉडा	235526
11.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, रिंगणीखाल	278236
12.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जयहरीखाल	262342
13.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, द्वारीखाल	276017
14.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, दुगड्डा	251230
15.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, यमकेश्वर	256201
16.	जिला प्रोवेशन अधिकारी	जिला प्रोवेशन अधिकारी, कचहरी परिसर, पौड़ी	221851
17.	अधीक्षक	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बदीनाथ मार्ग, श्रीनगर	
18.	अधीक्षक	रा0 डा0 भीमराव अम्बेडकर बालक छात्रावास, पौडी	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, जनपद–उत्तरकाशी

क्र. सं.	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टैलीफोन/ ई. मेल
1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	जिला समाज कल्याण कार्यालय, विकास भवन, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	01374–223731
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, मोरी	
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, नौगाँव	
4	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, चिन्यालीसौड	
5	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, डुण्डा	
6	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, भटवाडी	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद–चमोली)

1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, पोखरी	
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, कर्णप्रयाग	
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जोशीमठ	
4	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, दशोली	
5	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, घाट	
6	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, गैरसैण	
7	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, नारायणबगड़	
8	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, देवाल	
9	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, थराली	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद–बागेश्वर)

क्र. सं.	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन/ ई. मेल
1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी बागेश्वर	05963–220055
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी गरूड़	05963–220015
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कपकोट	05963–253036
4	प्रधानाचार्य	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काण्डा रोड़, बागेश्वर	05963–221234
5	अधीक्षिका	राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय, तहसील रोड़, बागेश्वर	05963–221549
6	अधीक्षक	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, नदीगॉव, बागेश्वर	05963–227234
7	सहायक प्रबन्धक	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0, बागेश्वर	05963–227234

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्याल (जनपद–हरिद्वार)

1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी बहदराबाद	
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी भगवानपुर	
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी नारसन	
4	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी रूड़की	
5	ग्राम विकास अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी लकसर	
6	सहायक प्रबन्धक	बहु0 वित्त एवं विकास निगम, विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार	01344–239743

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद–नैनीताल)

1.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी भीमताल	
2.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी ओखलकांडा	
3.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी हल्द्वानी	

4.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कोटाबाग	
5.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी रामनगर	
6.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	तहसील परिसर, हल्द्वानी।	
7.	सहायक प्रबन्धक	बहु0वित्त एवं विकास निगम, नैनीताल	
8.	प्रधानाचार्य	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पाइन्स, नैनीताल	05942–235199
9.	अधीक्षक	राजकीय छात्रावास बालक, पाइन्स, नैनीताल	
10.	अधीक्षक	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल	
11.	अधीक्षक	राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी–नैनीताल	
12.	अधीक्षक	राजकीय महिला शरणालय, हल्द्वानी–नैनीताल	05946–2554650
13.	अधीक्षक	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, हल्द्वानी–नैनीताल	
14.	प्रधानाचार्य	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालधनचौड–रामनगर(नैनीताल)	
15.	अधीक्षिका	शिशुसदन, हल्द्वानी–नैनीताल	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद–चम्पावत)

1.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी पाटी	
2.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी बाराकोट	
3.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी चम्पावत	
4.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी लोहाघाट	
5.	सहायक प्रबन्ध	उत्तरांचल बहु0 वित्त एवं विकास निगम लि0, चम्पावत	
6.	अधीक्षक	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, लोहाघाट	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद–ऊधमसिंह नगर)

1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– जसपुर	
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– काशीपुर	
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– बाजपुर	
4	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– गदरपुर	
5	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– रूद्रपुर	
6	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– सितारगंज	
7	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– खटीमा	
8	अधीक्षक	राजकीय जनजाति छात्रावास, काशीपुर	
9	अधीक्षक	राजकीय जनजाति छात्रावास, खटीमा	
10	अधीक्षक	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रूद्रपुर	
11	अधीक्षक	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गूलरभोज	
12	अधीक्षक	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा	
13	अधीक्षिका	राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, खटीमा	
14	प्रधानाचार्या	राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0बालिका विद्यालय, गूलरभोज	
15	प्रधानाचार्य	राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, गदरपुर	
16	प्रधानाचार्य	राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, बिडौरा–सितारगंज	
17	प्रधानाचार्य	राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, खटीमा	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद–रूद्रप्रयाग)

1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– अगस्तमुनि	
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– जखोली	
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी– उखीमठ	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद–पिथौरागढ़)

1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी (मु0)	कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ	05964–227475
2	सहा0स0क0 अधि0 / सहायक प्रबन्धक	उत्तरांचल बहु0वित्त एवं विकास निगम, पिथौरागढ	05964–225444
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी–मुनस्यारी	
4	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी–धारचूला	
5	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी–गंगोलीहाट	
6	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी–बेरीनाग	
7	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी–मूनाकोट	
8	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी–डीडीहाट	
9	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी–कनालीछीना	
10	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी–विण	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद–टिहरी)

1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, छाम–टिहरी	01376–287932
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, जौनपुर–टिहरी	01376–246302
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, भिलंगना–टिहरी	01379–258522
4	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, चम्बा–टिहरी	01376–255254
5	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापनगर–टिहरी	01379–262229
6	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, देवप्रयाग, टिहरी	01378–252312
7	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, कीर्तिनगर–टिहरी	01370–260109
8	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, जाखणीधार–टिहरी	01376–277224
9	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, फकोट–टिहरी	01378–223786
10	अधीक्षक	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, कैमरा–कैमर	दूरभाष नही है
11	अधीक्षिका	राकीय नारी निकेतन, थत्यूड–जौनपुर	01376–246346
12	सहायक अधीक्षिका	जिला शरणालय, नरेन्द्रनगर–टिहरी	01378–227167
13	सहायक अध्यापिका	शिशुशाला केन्द्र, नरेन्द्र नगर	

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद–अल्मोड़ा)

1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, हवालबाग	05962–241106
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, ताकुला	
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, धोलादेवी	05962–271009,
4	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, भैसियाछाना	05962–262120
5	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, लमगड़ा	05962–256022
6	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, भिकियासैण	05962–24009
7	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, चौखुटिया	05966–246033
8	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, ताड़ीखेत	05966–264238
9	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, स्यालदे	05966–247451
10	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, सल्ट	05966–238188

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद–देहरादून)

1	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, डोईवाला	2695020
2	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, रायपुर	2781673
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, सहसपुर	2697632
4	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, विकासनगर	250905
5	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, कालसी	275021
6	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, चकराता	272322

कार्यालय ज्ञाप

सूचना जन अधिकार अधिनियम–2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :–

1. निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल हल्द्वानी–नैनीताल में लोक सूचना अधिकारी के कार्य निदेशालय के सहायक निदेशक द्वारा सम्पन्न यिका जायेगा एवं इस निमित उन्हें नामांकित किया जाता है।

2. सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य जिला प्रोवेशन अधिकारी (मु0) द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे एवं इस निमित्त उन्हें नामांकित किया जाता है।

3. उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर एक पंजिका खोली जायेगी जिसमें उचित कार्यवाही यथा–आवेदन प्रपत्र देने की तिथि अंकित की जायेगी, सूचना कितनी अवधि में उपलब्ध करायी जानी का अंकन किया जायेगा व सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने की तिथि का भी अंकन किया जायेगा।

प्रत्येक माह के अंत में पंजिका में लम्बित एवं निस्तारित आवेदन पत्रों का विवरण तैयार किया जायेगा, जिसे निदेशक, समाज कल्याण उत्तरांचल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा व सूचना प्रतिमाह 3 तारीख तक शासन को प्रेषित की जायेगी, यह पंजिका प्रत्येक अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी।

लोक सूचना अधिकारी व सहायक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील निदेशक समाज कल्याण उत्तरांचल के समक्ष दायर की जायेंगी जिसमें निदेशक समाज कल्याण अपील अथारिटी होंगे प्राप्त समस्त अपीलों को एक पंजिका में रखा जायेगा जिसमें अपील से सम्बन्धित विवरण व अन्य आवश्यक सूचनायें अंकित की जायेगी व अपील निस्तारण की तिथि भी अंकित की जायेगी यह पंजिका निदेशक के आशुलिपिक श्री के0एस0 नेगी के पास रहेगी तथा प्रत्येक अपील की पंजिका अलग–अलग खोली जायेगी जिसमें अपीलों की तिथियों का विवरण भी अंकित किया जायेगा।

समस्त 13 जनपदों में जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रत्यक जनपद में लोक सूचना अधिकारी होंगे एवं इस निमित्त उन्हें नामांकित कया जाता है तथा प्रत्येक जनपद में विकासखण्ड स्तर पर तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे एवं उन्हें इस निमित नामांकित किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपदों में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों व अधीक्षक/प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मशाला अधीक्षक, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों के अधीक्षक/प्रबन्धक, विकलांग कर्मशालाओं के अधीक्षक, जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला), राजीय नारी निकेतन, राजकीय बालिका निकेतन, राजकीय शिशु सदन, राजकीय संरक्षण गृह राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी, राजकीय किशोर न्याय बोर्ड, राजकीय महिला आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, राजकीय बाल गृह राजकीय .....गृह महिला मूल्यांकन केन्द्र, दहेज प्रतिशोध अधिकारी व उद्धार अधिकारी संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबन्धक, सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे।

उक्त वर्णित सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर एक संस्था में एक पंजिका रखी जायेगी जिसका प्रतिमाह जिला समाज कल्याण अधिकारियें द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समस्त संस्थाओं/जिला कार्यालयों का एक संयुक्त विवरण तैयार कर प्रत्येक माह के अंत में संस्थावार पंजिका में लम्बित एवं निस्तारित आवेदन पत्रों का विवरण तैयार कर निदेशक, समाज कल्याण उत्तरांचल एवं शासन को प्रेषित किया जायेगा।

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी स्वयं/अपने अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से सूचना जन अधिकार अधिनियम–2005 का कार्यान्वयन सुव्यवस्थित ढंग सुनिश्चित करेंगे।

उक्त वर्णित लोक सूचना अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील निदेशक, समाज कल्याण (यदि शासन द्वारा जनपद स्तर पर किसी अधिकारी को नामांकित नहीं किया जाता है) के समक्ष दायर की जायेगी, इस निमित जनपदवार अपील सम्बन्धी पंजिका का रखरखाव निदेशक के आशुलिपिक द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे,

(कुणाल शर्मा)
निदेशक,

निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल, हल्द्वानी–नैनीताल

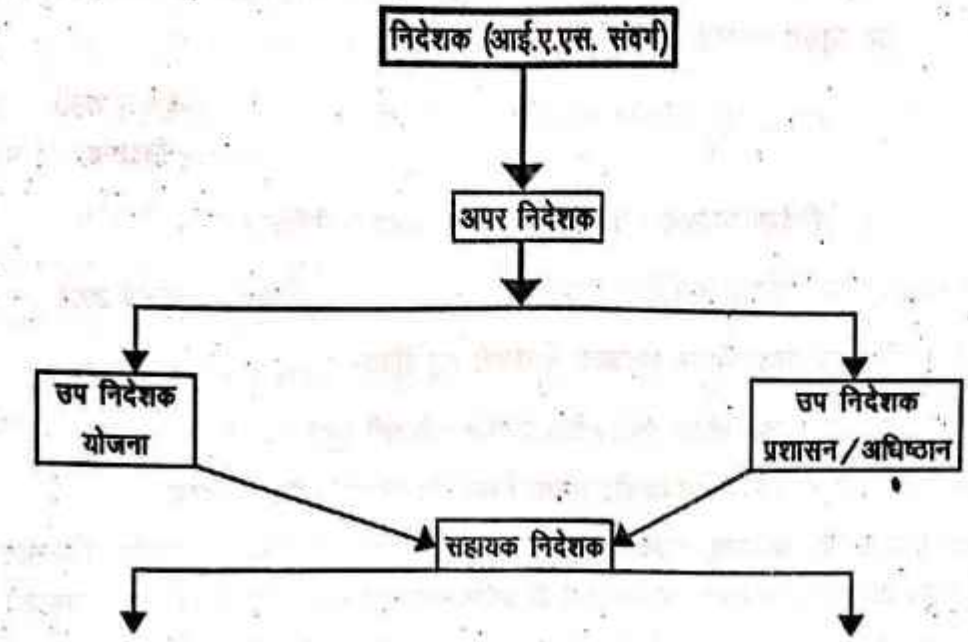
पत्र संख्या–1432/स.क./एस.टी./स.ज.अ./2005–06 दिनांक 20 जुलाई 2005

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्री आर.पी. पंत, सहायक निदेशक (मु0)/जि0 प्रोवशन अधिकारी (मु0)
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/समस्त जिला प्रोवशन अधिकारी उत्तरांचल।
3. समस्त प्रधानाचार्य/अधीक्षक/प्रबन्धक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय/छात्रावास/विकलांग कर्मशाला/परिवीक्षा सैक्टर (महिला कल्याण) के अधीन संचालित समस्त संस्था अधीक्षक/प्रबन्धक।
4. सचिव, समाज कल्याण उत्तरांचल शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

प्रस्तावित निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल राज्य के अधिष्ठान का विवरण



जिला समाज कल्याण अधिकारी (जनपद स्तर)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी (ब्लाक स्तर)

1.	लेखाकार	01
2.	वैयक्तिक सहायक	03
3.	आशुलिपिक	04
4.	मुख्य सहायक	02
5.	मुख्य लिपिक	05
6.	कनिष्ट सहायक	04
7.	जीप चालक	06
8.	चतुर्थ श्रेणी/स्वच्छक	06

कार्यालय स्टाफ	योग	31
अधिकारी वर्ग	योग	04
निदेशालय हेतु कुल प्रस्तावित पद		35

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	नगर/जनपद का नाम	स्वीकृत क्षमता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
क.	अनुसूचित जाति कल्याण सैक्टर :			
1.	राज.आ0प0विद्यालय :1 से 8	भीमताल, चमोली	175	स्वयं का भवन
2.	–तदैव–1 से 5	श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल	60	किराये का भवन
3.	–तदैव–1 से 5	देहरादून	60	स्वयं का भवन
4.	–तदैव–1 से 5	जैती, अल्मोड़ा	60	सरकारी भवन पर, परन्तु नये भवन निर्माण का प्रस्ताव है।
5.	आई.टी.आई.	रुद्रपुर–उधमसिंहनगर	160	स्वयं का भवन
6.	–तदैव–	पाइन्स, नैनीताल	160	स्वयं का भवन
7.	–तदैव–	मालधन चौड़, रामनगर	48	निर्माणाधीन
8.	–तदैव–	बागेश्वर	48	निर्माणाधीन
9.	छात्रावास – बालक	पौड़ी गढ़वाल	48	स्वयं का भवन
10.	–तदैव–	चमियाला, टिहरी	48	स्वयं का भवन
11.	–तदैव–	गोपेश्वर, चमोली	48	स्वयं का भवन
12.	–तदैव–	उत्तरकाशी	48	स्वयं का भवन
13.	–तदैव–	देहरादून	48	स्वयं का भवन
14.	–तदैव–	देहरादून	48	स्वयं का भवन
15.	–तदैव–	हरिद्वार	48	स्वयं का भवन
16.	–तदैव–	पाइंस, नैनीताल	48	स्वयं का भवन
17.	–तदैव–	सैनिक विद्यालय, नैनीताल	48	स्वयं का भवन
18.	–तदैव–	अल्मोड़ा	48	स्वयं का भवन किराये के भवन पर
19.	–तदैव–	चम्पावत	48	स्वयं का भवन
20.	–तदैव–	पिथौरागढ़	48	स्वयं का भवन
21.	–तदैव–	रुद्रप्रयाग	48	निर्माणाधीन
22.	–तदैव–	बागेश्वर	48	निर्माणाधीन
23.	छात्रावास – बालिका	पिथौरागढ़	48	स्वयं का भवन
24.	–तदैव–	पौड़ी गढ़वाल	48	स्वयं का भवन
25.	–तदैव–	उत्तरकाशी	48	स्वयं का भवन
26.	–तदैव–	मसूरी, देहरादून	48	स्वयं का भवन

ख. जनजाति कल्याण सेक्टर :				
27.	राज0मा0प0विद्या0–लिका 1 से 5	लालढांग, हरिद्वार	150	भवन निर्माणाधीन
28.	राज0आ0प0विद्या0–बालक 6 से 8	लालढांग, हरिद्वार	105	भवन निर्माणाधीन
29.	–तदैव– 6 से 10	त्यूनी, देहरादून	175	भवन निर्माणाधीन
30.	–तदैव– 6 से 10	अम्बाड़ी, देहरादून	175	स्वयं का भवन
31.	राज0आ0प0विद्या0– बालिका 1 से 10	लांघापोखरी, देहरादून	300	स्वयं का भवन/ विस्तार
32.	–तदैव– 6 से 10	लाखा मण्डल, देहरादून	175	
33.	–तदैव– 6 से 8	खटीमा, उधमसिंहनगर	105	किराये पर भूमि नहीं
34.	रा0आ0प0विद्या0, बालक 1 से 10	खटीमा, उधमसिंहनगर	245	स्वयं का भवन
35.	–तदैव– 6 से 10	गूलरभोज, उधमसिंहनगर	185	स्वयं का भवन/विस्तार
36.	–तदैव– 6 से 10	विडोरा, उधमसिंहनगर	175	भवन निर्माणाधीन
37.	–तदैव– 6 से 10	गदरपुर, उधमसिंहनगर	175	स्वयं का भवन/विस्तार
38.	–तदैव– 6 से 10	बलुवाकोट, पिथौरागढ़	235	भवन निर्माणाधीन
39.	–तदैव– 6 से 10	मुनस्यारी, पिथौरागढ़	175	भवन निर्माणाधीन
40.	रा0आ0प0विद्या0, बालिका–1 से 10	गोठी, पिथौरागढ़	310	किराये पर, भूमि नहीं
41.	रा0आ0प0विद्या0, बालक–6 से 10	जोशीमठ, चमोली	175	भवन निर्माणाधीन
42.	आई.टी.आई.	चकराता, देहरादून	32	स्वयं का भवन
43.	–तदैव–	खटीमा, उधमसिंहनगर	48	स्वयं का भवन
44.	–तदैव–	गूलरभोज, उधमसिंहनगर	32	स्वयं का भवन
45.	छात्रावास–बालक	गोपेश्वर, चमोली	50	स्वयं का भवन
46.	–तदैव–	धारचूला, पिथौरागढ़	50	स्वयं का भवन
47.	–तदैव–	खटीमा, उधमसिंहनगर	50	स्वयं का भवन
48.	–तदैव–	काशीपुर, उधमसिंहनगर	50	स्वयं का भवन
ग. समाज कल्याण सेक्टर :				
49.	वृद्ध एवं अशक्त गृह	गोपेश्वर, चमोली	50	किराये का भवन
50.	वृद्ध एवं अशक्त गृह	बागेश्वर	50	निर्माणाधीन
51.	भिक्षुक गृह	हरिद्वार	200	किराये पर/भवन निर्माणाधीन
घ. परिवीक्षा सेक्टर :				
52.	बाल गृह	हरिद्वार	30	निर्माणाधीन
53.	विशेष गृह	हरिद्वार	30	निर्माणाधीन
54.	सम्प्रेक्षण गृह	उत्तरकाशी	30	निर्माणाधीन
55.	सम्प्रेक्षण गृह	पौड़ी	30	निर्माणाधीन
56.	नारी निकेतन	देहरादून	30	निर्माणाधीन
अ. अल्पसंख्यक कल्याण सेक्टर :				
57.	हज हाउस	रुड़की, हरिद्वार		निर्माणाधीन

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तरांचल शासन
(समाज कल्याण विभाग)
संख्या – 68, 2001
देहरादून दिनांक.....मार्च 2001

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 21 मार्च, 2001 को सम्पन्न हुई मंत्रि परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के दो मण्डलों उप निदेशक समाज कल्याण, परियोजना निदेशक जनजाति विकास, सहायक निदेशक समाज कल्याण एवं जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी जनजाति विकास परियोजना एवं उनके संगठनों में उपलब्ध अन्तर्निहित पदों को पुनर्गठित करते हुए समाज कल्याण निदेशालय के संलग्नानुसार संगठनात्मक संरचना की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। जनपदों में कार्यरत जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी एवं उनके संगठनों में कार्यरत कार्मिकों को अपने–अपने मूल विभागों में प्रत्यावर्तित किये जाने की भी स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं। विभाग के पुर्नगठटन के फलस्वरूप जनपदों में कार्यरत अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) का पद जिला समाज कल्याण अधिकारी में विलीनीकरण करते हुए अब जनपदों में समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाओं का संचालन जिला समाज कल्याण अधिकारी करेंगे, तथा उन्हें इस निमित्त आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है।

2. मंडलीय जनपदीय कार्यालयों की पुर्नगठित होने के पश्चात इस कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों से विकल्प लेकर निदेशालय अथवा अन्यत्र समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। नवसृजित पदों के पद पुनर्पदस्थापन (रि. डिप्लायमेंट) अथवा प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा।

3. अग्रेतर इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसमें अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारमी की गई या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा। निदेशालय में पदों का विवरण इस कार्यालय ज्ञाप के साथ संलग्न कर अंकित किया गया है।

आज्ञा से,

(डॉ. आर. एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 58/समाज कल्याण/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
4. निजी सचिव मा. मंत्री जी उद्यान, समाज कल्याण, रेशम एवं तकनीकी शिक्षा
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
7. अपर निदेशक, समाज कल्याण शिविर कार्यालय, देहरादून।
8. संयुक्त कवासि आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल।
11. उपनिदेशक समाज कल्याण गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी।
13. समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)।
14. समस्त जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी।
15. समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी।
16. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी।
17. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुन्दर लाल)
अपर सचिव

कार्यालय ज्ञाप

सूचना जन अधिकार अधिनियम–2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :–

1. निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल हल्द्वानी–नैनीताल में लोक सूचना अधिकारी के कार्य निदेशालय के सहायक निदेशक द्वारा सम्पन्न यिका जायेगा एवं इस निमित उन्हें नामांकित किया जाता है।

2. सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य जिला प्रोवेशन अधिकारी (मु0) द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे एवं इस निमित्त उन्हें नामांकित किया जाता है।

3. उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर एक पंजिका खोली जायेगी जिसमें उचित कार्यवाही यथा–आवेदन प्रपत्र देने की तिथि अंकित की जायेगी, सूचना कितनी अवधि में उपलब्ध करायी जानी का अंकन किया जायेगा व सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने की तिथि का भी अंकन किया जायेगा।

प्रत्येक माह के अंत में पंजिका में लम्बित एवं निस्तारित आवेदन पत्रों का विवरण तैयार किया जायेगा, जिसे निदेशक, समाज कल्याण उत्तरांचल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा व सूचना प्रतिमाह 3 तारीख तक शासन को प्रेषित की जायेगी, यह पंजिका प्रत्येक अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी।

लोक सूचना अधिकारी व सहायक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील निदेशक समाज कल्याण उत्तरांचल के समक्ष दायर की जायेंगी जिसमें निदेशक समाज कल्याण अपील अथारिटी होंगे प्राप्त समस्त अपीलों को एक पंजिका में रखा जायेगा जिसमें अपील से सम्बन्धित विवरण व अन्य आवश्यक सूचनायें अंकित की जायेगी व अपील निस्तारण की तिथि भी अंकित की जायेगी यह पंजिका निदेशक के आशुलिपिक श्री के0एस0 नेगी के पास रहेगी तथा प्रत्येक अपील की पंजिका अलग–अलग खोली जायेगी जिसमें अपीलों की तिथियों का विवरण भी अंकित किया जायेगा।

समस्त 13 जनपदों में जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रत्यक जनपद में लोक सूचना अधिकारी होंगे एवं इस निमित्त उन्हें नामांकित कया जाता है तथा प्रत्येक जनपद में विकासखण्ड स्तर पर तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे एवं उन्हें इस निमित नामांकित किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपदों में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों व अधीक्षक/प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मशाला अधीक्षक, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों के अधीक्षक/प्रबन्धक, विकलांग कर्मशालाओं के अधीक्षक, जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला), राजकीय नारी निकेतन, राजकीय बालिका निकेतन, राजकीय शिशु सदन, राजकीय संरक्षण गृह राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी, राजकीय किशोर न्याय बोर्ड, राजकीय महिला आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, राजकीय बाल गृह राजकीय विश्व महिला मूल्यांकन केन्द्र, दहेज प्रतिषेध अधिकारी व उद्धार अधिकारी संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबन्धक, सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे।

उक्त वर्णित सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर एक संस्था में एक पंजिका रखी जायेगी जिसका प्रतिमाह जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समस्त संस्थाओं/जिला कार्यालयों का एक संयुक्त विवरण तैयार कर प्रत्येक माह के अंत में संस्थावार पंजिका में लम्बित एवं निस्तारित आवेदन पत्रों का विवरण तैयार कर निदेशक, समाज कल्याण उत्तरांचल एवं शासन को प्रेषित किया जायेगा।

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी स्वयं/अपने अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से सूचना जन अधिकार अधिनियम–2005 का कार्यान्वयन सुव्यवस्थित ढंग सुनिश्चित करेंगे।

उक्त वर्णितलोक सूचना अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील निदेशक, समाज कल्याण (यदि शासन द्वारा जनपद स्तर पर किसी अधिकारी को नामांकित नहीं किया जाता है) के समक्ष दायर की जायेगी, इस निमित जनपदवार अपील सम्बन्धी पंजिका का रखरखाव निदेशक के आशुलिपिक द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे,

(कुणाल शर्मा)
निदेशक,

निदेशालय समाज कल्याण उत्तरांचल, हल्द्वानी–नैनीताल

पत्र संख्या–1432/स.क./एस.टी./स.ज.अ./2005–06

दिनांक 20 जुलाई 2005

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्री आर.पी. पंत, सहायक निदेशक (मु0)/जि0 प्रोवशन अधिकारी (मु0)
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/समस्त जिला प्रोवशन अधिकारी उत्तरांचल।
3. समस्त प्रधानाचार्य/अधीक्षक/प्रबन्धक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय/छात्रावास/विकलांग कर्मशाला/परिवीक्षा सैक्टर (महिला कल्याण) के अधीन संचालित समस्त संस्था अधीक्षक/प्रबन्धक।
4. सचिव, समाज कल्याण उत्तरांचल शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

संलग्नक : 5

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तरांचल हेतु प्रस्तावित पदों का संरचना विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	वर्तमान में विभिन्न कार्यालयों में स्वीकृत पद	कार्यरत पद	पुनर्गठित निदेशालय हेतु वेतनमान सहित	समायोजन कहां से कहां होगा प्रस्तावित पद
1.	निदेशक	–	–	–	आई.ए.एस. संवर्ग
2.	अपर निदेशक	1	–	1 14300–18300	वर्तमान निदेशालय से
3.	उप निदेशक	3	2	2 10000–15200	मण्डलों से
4.	सहायक निदेशक	1	–	1 8000–13500	वर्तमान निदेशालय से
5.	वैयक्तिक सहायक	8	6	2 5500–9000	मण्डल/परियोजना में कार्यरत आशुलिपिकों की पदोन्नति सं. 1 निदेशक के साथ 1 अपर निदेशक के साथ
				4 4000–6000	प्रस्तावित निदेशालय में 2 उपनिदेशकों के साथ 2 जनपदों में समायोजित
6.	लेखाकार	1	–	1 5000–8000	वर्तमान निदेशालय से
9.	वरिष्ठ सहायक	2	2	2 4500–7000	मण्डलों से
10.	वरिष्ठ लिपिक	10	8	4 4000–6000	4 पद मण्डलों से निदेशालय में, 4 पद जनपदों में,
9.	कनिष्ट लिपिक	8	6	4 3050–4590	4 पद मण्डल/परियोजनाओं से निदेशालय में 2 पद जनपदों में
10.	जीप चालक	8	5	3 3050–4590	3 पद मण्डल परियोजनाओं से निदेशालय में 2 पद जनपदों में,
11.	चतुर्थ श्रेणी/ स्वच्छक	20	18	6 2550–3200	6 पद मण्डल परियोजनाओं से निदेशालय में 12 पद जनपदों में,
	योग	62	47	30	

प्रेषक,

डॉ. आर. एस. टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तरांचल देहरादून

समाज कल्याण विभाग — देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2001

विषय : उत्तरांचल राज्य में समाज कल्याण के संरचनात्मक ढ़ांचे का पुर्नगठन।

महोदय,

प्रदेश के गठन के पश्चात उत्तरांचल में अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति, अल्प संख्यक एवं विकलांग कल्याण को पुर्नगठित करते हुए समाज कल्याण विभाग का ढ़ांचा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 58/2001 देहरादून दिनांक 27 मार्च 2001 द्वारा जारी किया गया था, उपरोक्त निदेशालय की पुनरीक्षित संरचना की श्री राज्यपाल निम्न संशोधन के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल का विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है, जनपदीय अधिकारियों पर विभागाध्यक्ष का सीधा नियंत्रण होगा।

3. प्रदेश के अपर निदेशक कार्यालय, उत्तरांचल एवं दोनों मण्डलीय कार्यालयों को पुर्नगठन के फलस्वरूप निदेशालय समाज कल्याण, उत्तरांचल में संविलीन किया जाता है, उपनिदेशक, जनजाति कल्याण गढ़वाल मण्डल एवं परियोजना निदेशक जनजाति परियोजना प्राधिकरण का पद समाप्त किया जाता है, उप निदेशक कार्यालय के स्टाफ को पुर्नगठित निदेशालय में समायोजित किया जाता है तथा परियोजना निदेशक एवं एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के स्टाफ को नवसृजित जनपदों/समाज कल्याण कार्यालयों/संस्थाओं/निदेशालय में समायोजित किया जाता है।

4. जनपद स्तर पर अब सभी कार्यक्रमों का दायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा, अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.) तथा एकीकृत जनजाति विकास परियोजना अधिकारी के पदों को समाप्त करते हुए वर्तमान में इन पदों के पदधारकों को वेतनमान सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर संविलीन किया जाता है, और इन पदों को मृत घोषित किया जाता है।

5. नवगठित राज्य में अल्प संख्यक कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/विकलांग कल्याण विभागों को पुनर्गठित करते हुए उनमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल विभागों को वापस कर दिया गया है, इस प्रकार उत्तरांचल में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना/जनजाति कल्याण एवं समाज कल्याण अधिष्ठान का एकीकरण किया जाता है, अतः इन अधिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों की संवर्गवार सम्मिलित वरिष्ठता सूची शासन/विभागाध्यक्ष स्तर से जारी की जाय।

6. पुनर्गठित ढांचके के फलस्वरूप अब निदेशालय एवं जनपद स्तर पर समाज कल्याण विभाग का दो स्तरीय ढांचा स्थापित किया जाता है।

6.1 निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के अलावा दो अपर निदेशक (एक पी.सी.एस. सवर्ग तथा एक विभागीय संवर्ग) दो उप निदेशक (विभागीय संवर्ग) एक सहायक निदेशक (विभागीय संवर्ग) के पद रहेंगे, विभागीय संवर्ग के सभी पद विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जायेंगे।

6.2 प्रस्तुत 6.1 में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर 3 पद वैयक्तिक सहायक, 4 पद आशुलिपिक, 2 पद वरिष्ठ सहायक, 4 पद वरिष्ठ लिपिक, 4 पद कनिष्ठ लिपिक, 6 पद जीप चालक, 9 पद चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत किये जाते हैं।

6.3 निदेशालय स्तर पर एक पद मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा संवर्ग) तथा एक वरिष्ठ सम्प्रेक्षक, एक पद लेखाकार, एक पक्ष सम्प्रेक्षक/लेखाकार, एक पद सहायक लेखाकार, एक पद लेखा लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर, एक पद वरिष्ठ लिपिक (कम्प्यूटर दक्ष) सह डाटा इन्ट्री आपरेटर, एक पद कनिष्ठ लिपिक (कम्प्यूटर दक्ष) सह डाटा इन्ट्री आपरेटर, के स्वीकृत किये जाते हैं

6.4 शासनादेश संख्या : 58/2001 दिनांक 27 मार्च, 2001 के द्वारा जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण विभागों को पुनर्गठित करते हुए इन विभागों से सम्बन्धित कार्य एवं समाज कल्याण के कार्यक्रमों के संचालन एवं उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, तहसील स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर तैनात सहायक विकास अधिकारी (स.क.) तथा जनजाति कल्याण निरीक्षक वेतनमान 4500–7000 एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक, तथा जनजाति कल्याण पर्यवेक्षक वेतनमान 3050–4590 को पुनर्गठित करते हुए अब उन्हें विकास खण्ड स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी ग्रेड–1 वेतनमान 4500–7000 तथा सहायक समाज कल्याण अधिकारी ग्रेड–2 वेतनमान 3050–4590 के पद नाम से तैनात किया जाता है।

अतः समाज कल्याण विभाग के निदेशालय स्तर तथा जनपद स्तर पर प्रदेश के निम्नानुसार पद रहेंगे :

क्रम सं.	पद नाम	वेतनमान	पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
	निदेशक	आई.ए.एस. संवर्ग		विभागाध्यक्ष
समूह–क				
1.	अपर निदेशक	पी.सी.एस. संवर्ग	1	निदेशालय स्तर पर
2.	अपर निदेशक	14300–18300	1	तदैव
3.	मुख्य वित्त अधिकारी	वित्त एवं लेखा संवर्ग	1	तदैव
4.	उप निदेशक	10000–15200	2	तदैव

समूह–ख				
4.	सहायक निदेशक	8000–13500	1	तदैव
समूह–ग				
5.	वैयक्तिक सहायक	5500–9000	3	तदैव
6.	लेखाकार	5000–8000	1	तदैव
7.	सम्प्रेक्षक	5000–8000	1	तदैव
8.	लेखाकार	4500–7000	1	तदैव
9.	सहायक लेखाकार	4500–7000	1	तदैव
10.	सहायक	4500–7000	2	तदैव
11.	लिपिक	4000–6000	4	तदैव
12.	लिपिक	4000–6000	4	तदैव
13.	लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर दक्ष)	4000–6000	1	तदैव
14.	वरिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर दक्ष)	4000–6000	1	तदैव
15.	कनिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर दक्ष)	3050–4590	1	तदैव
16.	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	4	तदैव
17.	जीप चालक	3050–4590	6	तदैव
18.	चतुर्थ श्रेणी कर्मी स्वच्छक/ चौकीदार	2550–4200	9	तदैव
	योग मुख्यालय		45	

जनपद स्तर/विभागीय संस्थाऐं

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
समूह–ख				
1.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	8000–13500	5	जनपद स्तर पर
		6500–10500	8	तदैव
2.	प्रधानाचार्य (आई.टी.आई.)	8000–13500	1	औ. प्रशिक्षण केन्द्र
3.	प्रधानाचार्य आ.प.वि.	6500–10500	12	आ.प.वि. जनजाति
4.	अधीक्षक/अधीक्षिका	5000–8000	1	वृद्ध अशक्त गृह
5.	अधीक्षक/अधीक्षिका	5000–8000	1	भिक्षुक गृह
6.	अधीक्षक/अधीक्षिका	5000–8000	5	आ.प.वि. सक
7.	अधीक्षक/अधीक्षिका	5000–8000	3	विकलांग कर्मशा.
8.	अधीक्षक/अधीक्षिका	5000–8000	15	आ.प.वि. जनजाति
समूह–ग				
9.	कार्यशाला अधीक्षक	5500–9000	3	आई.टी.आई. ज.जा.
10.	अनुदेशक	5000–8000	6	तदैव

11.	फोरमैन	5000–8000	1	तदैव
12.	ग्रुप अनुदेशक	5000–8000	3	तदैव
13.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी ग्रेड–1	5000–8000	66	ब्लाक स्तर
14.	सहायक समाज कल्याण अधिकार ग्रेड–2	3050–4590	48	ब्लाक स्तर
15.	वरिष्ठ सहायक	4500–7000	6	जनपद स्तर
16.	वर्कशाप सुपरवाइजर	4500–7000	2	आई.टी.आई.
17.	सहकारिता निरीक्षक	4500–7000	2	ज.जा.सं. संघ
18.	सहायक प्रबन्धक	4500–7000	4	छात्रावास ज.जा.
19.	सहायक अधीक्षक	4500–7000	9	छात्रावास स.क.
20.	सहायक अधीक्षक (महिला)	4500–7000	3	तदैव
21.	सहायक प्रबन्धक	4500–7000	1	औद्योगिक आस्थान
22.	वरिष्ठ प्रशिक्षक	4500–7000	8	आई.टी.आई. (स.क.)
23.	मनोवैज्ञानिक	4500–7000	7	आई.टी.आई. (ज.जा.)
24.	सहायक अध्यापक	4500–7000	4	भिक्षुक गृह
25.	पर्यवेक्षक	4500–7000	2	तदैव
26.	सहायक अध्यापक (एल.टी.)	4500–7000	71	आ.प.वि. (ज.जा.)
27.	नर्स/कम्पाउण्डर	4500–7000	21	आ.प.विभि. गृह
28.	लेखा लिपिक	4000–6000	10	जनपद स्तर
29.	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	61	जनपद स्तर–29 संस्थाओं में–32
30.	आशुलिपिक (ज.जा.)	4000–6000	4	जनपद स्तर
31.	क्रय–विक्रय पर्यवेक्षक	4000–6000	2	दो जनपदों में
32.	सहायक अध्यापक (सी.टी.)	4000–6000	51	आ.प.वि.ज.जा.–45
	एक विज्ञान अध्यापक			आ.प.वि.ज.जा.–6
33.	सहायक अध्यापक (बेंतकला)	4000–6000	1	भिक्षुक गृह
34.	व्यायाम प्रशिक्षक	4000–6000	10	आ.प.वि.ज.जा.
35.	काष्ठ कला अध्यापक	4000–6000	4	आ.प.वि.ज.जा.
36.	सिलाई अध्यापक	4000–6000	14	तदैव
37.	कताई बुनाई अध्यापक	4000–6000	1	तदैव
38.	कला अध्यापक	4000–6000	6	तदैव
39.	सहायक अध्यापक (संगीत)	4000–6000	10	तदैव
40.	ग्राम विकास अधिकारी	3200–4900	108	स.क.95 ज.जा.–11
41.	कनिष्ठ प्रशिक्षक	3200–4900	6	आई.टी.आई. (स.क.)
42.	क्राफ्ट अध्यापक	3200–4900	1	आ.प.वि. (स.क.)
43.	प्रसार अध्यापक	3200–4900	1	तदैव
44.	प्रशिक्षक	3200–4900	1	भिक्षुक गृह
45.	सहायक अध्यापक (एच.टी.सी.)	3200–4900	22	आ.प.वि. ज.जा.–13 आ.प.वि. ज.जा.–9
46.	गृहमाता	3200–4900	11	आ.प.वि. ज.जा.–6 आ.प.वि.ज.जा.–5

47.	सहायक अधीक्षक	3200–4900	3	आ.प.वि. (ज.जा.)
48.	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	88	जनपद/संस्थाऐं
49.	कनिष्ठ लेखा लिपिक	3050–4590	8	जनपद स्तर
50.	प्रशिक्षक सिलाई/काष्ठ	3050–4590	2	भिक्षुक गृह
51.	शिल्प प्रशिक्षक	3050–4590	9	विकलांग कर्मशाला
52.	सेल्समैन	3050–4590	3	तदैव
53.	जीप चालक	3050–4590	13	जनपद स्तर
समूह–ख			0	
54.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2550–3200	313	जनपद/संस्थाऐं
55.	चतुर्थ श्रेणी नियत वेतन	2550 Fix Pay	21	तदैव
	कुल योग (जनपद स्तर/संस्थाऐं) महायोग :	1100	1145	

भवदीय

(डा. आर. एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या 927/स.क./2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री उद्यान, समाज कल्याण, उत्तरांचल को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल/नैनीताल।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल शासन/अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.) /परियोजनाधिकारी (जनजाति), उत्तरांचल।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुन्दर लाल)
अपर सचिव

9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
12. समस्त उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी, उत्तरांचल।
13. समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तरांचल।
14. समस्त अधीक्षक/अधीक्षिका, प्रोवेशन एवं महिला कल्याण, उत्तरांचल।
15.. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुन्दर लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
(समाज कल्याण विभाग)
संख्या 926/स.क./वै.स./2001
देहरादून दिनांक दिसम्बर 26, 2001

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 6.11.2001 को सम्पन्न हुई मा. मंत्रि परिषद की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार महिला कल्याण विभाग को समाज कल्याण विभाग में संविलीन करने की श्री राज्यपाल, महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा संलग्नक में स्वीकृत महिला कल्याण के पदों को निदेशालय, स्तर पर तथा संलग्नक–2 में स्वीकृत पदों को जनपद स्तर पर रखे जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. जिन जनपदों में जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यरत नहीं हैं उनमें प्रोवेशन अधिकारियों से सम्बन्धित समस्त कार्य अब जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा। प्रोवेशन एवं महिला कल्याण विभाग से सम्बन्धित समस्त आहरण–वितरण अधिकार अब लिा समाज कल्याण अधिकारियों में निहित होगा। इस प्रकार जनपद स्तर पर भी महिला कल्याण विभाग जिला समाज कल्याण अधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा।

3. अग्रेत्तर इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसमें अब तक उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की ई या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

भवदीय,

(डॉ. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 926/स. क./2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
4. निजी सचिव मा. मंत्री जी उद्यान, समाज कल्याण, उत्तरांचल, को मा. मंत्री जी के अवलाकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
7. निदेशक, समाज कल्याण उत्तरांचल, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।

संलग्नक–1

संख्या 926/स. क./वै.स./2001 देहरादूनदिनांक दिसम्बर 26, 2001 को संलग्नक

महिला कल्याण विभाग के स्वीकृत पदों का विवरण जो समाज कल्याण निदेशालय में संविलीन किये गये।

1.	उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी (वेतनमान 8000–13500)	1 (एक)
2.	प्रोवेशन अधिकारी (5000–8000)	1 (एक)
3.	आशुलिपिक (4000–6000)	2 (दो)
4.	कनिष्ठ लिपिक (3050–4590)	4 (चार)
5.	वाहन चालक (3050–4590)	2 (दो)
6.	चतुर्थ श्रेणी (2550–3200)	5 (पांच)
	कुल–	15 (पन्द्रह)
	अधिकारी–	02 (दो)
	कर्मचारी वर्ग–	13 (तेरह)

(डॉ. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संलग्नक–1

संख्या 926/स. क./वै.स./2001 देहरादून दिनांक दिसम्बर 26, 2001 को संलग्नक

महिला कल्याण विभाग के जनपद स्तरीय स्वीकृत पद जो समाज कल्याण निदेशालय में संविलीन किये गये।

1.	जिला प्रोवेशन अधिकारी (6500–10500)	4	(चार)
2.	प्रोवेशन अधिकारी (5000–8000)	1	(एक)
3.	अधीक्षक/अधीक्षिका	9	(नौ)
4.	सहायक अधीक्षक/सहायक अधीक्षिका	11	(ग्यारह)
5.	वरिष्ठ लिपिक (4000–6000)	8	(आठ)
6.	कनिष्ठ लिपिक (3050–4590)	23	(तेईस)
7.	मैटर्न	5	(पांच)
8.	नर्स	10	(दस)
9.	क्राफ्ट प्रशिक्षक/प्रशिक्षिका	17	(सत्रह)
10.	सहायक अध्यापिका	15	(पन्द्रह)
11.	संगीत अध्यापिका	2	(दो)
12.	अन्वेषक	1	(एक)
13.	वर्क शॉप सुपरवाइजर	1	(एक)
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	104	(एक सौ चार)
	कुल	211	(दो सौ ग्यारह)

(डॉ. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त